आज का विचार

याद रखिए आपको अपना हक वहीं दिखाना चाहिए जहां आपके शब्दों और भावनाओं की कद्र हो।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 80, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

चंडीगढ़ केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है; भाजपा दफ्तर के बाहर हमले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार: भगवंत मान

अगर चंडीगढ़ में हुई घटना के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो केंद्र को चंडीगढ़ पंजाब सरकार को सौंप देना चाहिए:मुख्यमंत्री

यज्ञांश शर्मा
संगरूर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि केंद्र के नियंत्रण में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश को सियासी दुष्प्रचार का आधार बनाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। यह स्पष्ट करते हुए कि इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की है, उन्होंने कहा कि अगर इस घटना को उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है तो केंद्र को अपनी ड्यूटी से भागने की बजाय चंडीगढ़ को पंजाब सरकार के हवाले कर देना चाहिए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शासन मॉडलों के बीच बड़े अंतर का हवाला देते हुए कहा कि जहां ह्यआपह्ल सरकार लोगों से वित्तीय बोझ घटा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आम जनता पर गैर-वाजिब ढंग से एंट्री टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने इस कदम को जन-विरोधी बताते हुए इसके हर स्तर पर सख्त विरोध का भरोसा दिया।

किसानों प्रति अपनी सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार आढ़तियों की मांगों को केंद्र सरकार के पास लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान भाईचारे के कंधे से कंधा लगा कर हमेशा खड़ी है और पहले के सफल सीजनों की तरह फसल की निर्विघ्न खरीद सुनिश्चित बनाएगी। गांव चीमा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोक अर्पण करने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि चंडीगढ़ का प्रबंधन पंजाब के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, फिर भी भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसान आंदोलन, पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) में आंदोलन या कोई भी ऐसा मुद्दा हो, भाजपा सारा दोष मेरे ऊपर थोपने को हमेशा तैयार रहती है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर बेबुनियाद और बेतुकी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए क्योंकि यह जगह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के अधिकार क्षेत्र के अधीन आती है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब चंडीगढ़ की मांग करता है तो इसे अलगाववादी विचारधारा बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार यू.टी. चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था कायम रखने के अपने फर्ज से हमेशा भागती रही है।

कांग्रेस की अगुवाई वाली हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स लगाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ ह्यआपह्ल सरकार टोल टैक्स खत्म करके आम आदमी को राहत दे रही है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग आम जनता पर अनाश्वयक टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम पूरी तरह गैर-वाजिब है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इसका हर स्तर पर जोरदार विरोध किया जाएगा।

किसानों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि उनकी सारी मांगें भारत सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ये मुद्दे पहले भी बार-बार केंद्र के समक्ष उठाए गए हैं और राज्य सरकार लगातार ऐसा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ह्यआपह्ल सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सुचारू और मुश्किल रहित खरीद सुनिश्चित बनाने के लिए दृढ़ है।

विकसित भारत के लक्ष्य के लिए पब्लिक सर्विस का निरंतर अपडेट जरूरी: मोदी

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम, संवेदनशील और आधुनिक प्रशासनिक तंत्र की अहम भूमिका होगी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह के अवसर पर कहा कि तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए देश की पब्लिक सर्विस को लगातार अपडेट करना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम, संवेदनशील और आधुनिक प्रशासनिक तंत्र की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी में वैश्विक व्यवस्थाएं तेजी से बदल रही हैं और भारत भी उसी गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को समयानुकूल बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी साधना सप्ताह इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कार्यशैली को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन व्यवस्था का मूल मंत्र नागरिक देवो भव है, जिसका अर्थ है कि नागरिक सर्वोपरि हैं। इस सोच के साथ सरकार सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सक्षम और नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत एक आकांक्षी समाज है, जहां हर नागरिक के अपने सपने और लक्ष्य हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में लगातार सुधार हो। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन कुछ नया सीखने की आदत विकसित करें और खुद को एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में ढालें। उन्होंने कहा कि निरंतर सीखने और आत्म-विकास से ही प्रशासनिक तंत्र मजबूत होगा और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले व्यवस्था में अधिकारी होने पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब समय कर्तव्य भावना को प्राथमिकता देने का है। उन्होंने कहा कि हर निर्णय लेने से पहले यदि अधिकारी अपने कर्तव्य के बारे में सोचेंगे, तो उसके परिणाम स्वतः ही अधिक प्रभावी होंगे और समाज पर सकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर निर्णय को भविष्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आज लिए गए निर्णय देश की विकास यात्रा को नई दिशा देंगे। एक व्यक्ति का आत्म-परिवर्तन ही संस्थागत परिवर्तन का आधार बन सकता है।

अच्छे प्रशासक को तकनीक और डेटा की सही जानकारी होनी चाहिए: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के परिवर्तन के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो केवल सेवा भाव से ही प्राप्त होती है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्य को सेवा के रूप में देखें और उसी भावना के साथ कार्य करें। तकनीक और डेटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में शासन और प्रशासन में तकनीक का व्यापक उपयोग हुआ है, जिससे सेवा वितरण में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के आगमन से यह बदलाव और तेज होने वाला है। उन्होंने कहा कि भविष्य का सफल प्रशासक वही होगा, जिसे तकनीक और डेटा की अच्छी समझ होगी। यह समझ निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगी। उन्होंने इस दिशा में क्षमता निर्माण और निरंतर प्रशिक्षण पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संघीय ढांचे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सफलता राज्यों की सामूहिक सफलता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अब अग्रणी, पिछड़े या बीमारू राज्यों जैसी पुरानी श्रेणियों से आगे बढ़ते हुए सभी राज्यों के बीच अंतर को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए साइलो सोच को खत्म करना होगा और बेहतर समन्वय तथा साझा समझ के साथ काम करना होगा। उन्होंने होल-ऑफ-गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे सभी सरकारी मिशनों को सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि यह संस्था सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह की पहल से आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगियों की एक मजबूत टीम तैयार होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम नागरिक के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय ही पूरे शासन का चेहरा होता है। ऐसे में अधिकारियों का व्यवहार और कार्यशैली ही लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत या कमजोर करती है।

जरूरतमंद के आवास और बीमार के इलाज की होगी व्यवस्था : योगी

एजेंसी (हि.स.)
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है।

गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 100 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ध्यान से उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से जुड़े मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में एक महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद मांगने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ आए बच्चों को चॉकलेट देकर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया।

भारत की पश्चिम एशिया के हालात पर नजर, हर स्थिति से निपटने को तैयार: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं।

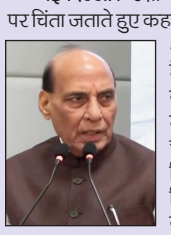

आज हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में बड़ा संघर्ष चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी है। कुछ लोग इस मौके पर कई तरह का झूठ फैला कर घबड़ाहट फैलाना चाहते हैं, जबकि भारत इस किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सैनिक सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम और तैयार है। यह समय पूरे देश के एकजुट होने का है। संकट के समय में भाजपा ने हमेशा देश का साथ दिया है। यह समय दलगत राजनीति करने का नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को एकसाथ आने का है।

राहुल गांधी ने चुनावी सभा में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

एजेंसी (हि.स.)
जोरहाट

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को असम पहुंचे कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर राजनीतिक हमले किये।

जोरहाट जिला के तिताबर में आयोजित एक चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जो भूमि आप लोगों से छीनी गई है, वह वापस दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम आपके जरिए उन्हें एक संदेश देना चाहते

हैं, भले ही हिमंत बिस्व सरमा माफी मांग लें, हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री और उनके परिवार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का परिणाम एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ेगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत डॉ. सरमा को सुरक्षा नहीं दे सकती। मैं जो कहता हूं, उसे करके दिखाऊंगा। यह भूमि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की भूमि, डॉ. भूपेन हजारिका की भूमि, जुबिन गर्ग की भूमि है। असम की आत्मा में था, असम के लिए इन महान लोगों ने सब कुछ दिया। सभी ने हिंसा से परहेज करके एकजुट रहने का संदेश दिया। लेकिन आपके मुख्यमंत्री इस सोच से बहुत दूर हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा, भ्रष्टाचार और डर फैलाना मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है। जुबिन गर्ग ने सभी की मदद की, प्रेम-भाईचारे की बात कही। ऐसे में देखा जाए तो एक ओर जुबिन गर्ग हैं तो ठीक उसके विपरीत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने चाय मजदूरों को 350 रुपये मजदूरी का वादा किया था। लेकिन 350 रुपये मजदूरी आपको मिली है या नहीं, यह एक सवाल है।

उन्होंने कहा कि हिमंत बिस्व सरमा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने आडानी को 18 हजार बीघा, अंबानी को 13 हजार बीघा भूमि, पतंजलि को 6 हजार बीघा भूमि दी।

भवानीपुर से ममता बनर्जी की हार पूरे बंगाल में परिवर्तन की शुरूआत होगी: शाह

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि यदि भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो पूरे बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले पूरे बंगाल का दौरा किया है और हर जगह लोगों में सरकार बदलने की इच्छा दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में तोलाबाजी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी और अवैध घुसपैठ जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सीमाओं को मजबूत किया जाएगा और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है वहां विकास हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है।

अमित शाह ने भवानीपुर के मतदाताओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि सामान्यतः कई सीटें जीतने के बाद परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार भवानीपुर की एक सीट की जीत भी पूरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं और इस बार उन्हें भवानीपुर में भी हार का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि इस बार कोई भी मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यकताओं की हत्या के आरोपों का भी उल्लेख करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कही।

भाजपा ही ऐसी सरकार दे सकती है जो किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों का भला कर सके: नायब सिंह सैनी

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से पंजाब की आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर बुधवार देर शाम मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब के आढ़तियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पंजाब में लगभग 40 हजार आढ़ती, करीब सवा लाख मुनीम तथा 6-7 लाख श्रमिक इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आढ़तियों के समक्ष आ रही दिक्कतों के चलते पंजाब में आढ़तियों की हड़ताल चल रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। सरकार से वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। फसल खरीद के इस सीजन में आढ़ती वर्ग के साथ-साथ लेबर तबका और किसान भी परेशान हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वयं कई बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं और वहां हर वर्ग चाहे किसान हो, व्यापारी हो या श्रमिक परेशान नजर आता है। समस्याओं के हल की तरफ वहां की आप पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और प्रदेश को ह्यकंगालह्ल बनाने का काम किया है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी समय है, पंजाब को वहां की जनता संभाल लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ही वहां ऐसी सरकार दे सकती है जो किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों का भला कर सके।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में किसानों की सभी

फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही आढ़तियों के कमीशन को भी समय-समय पर बढ़ाया गया है, ताकि उनकी आय और सम्मान दोनों सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में गेहूं पर आढ़तियों को 55 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया है जो कि पंजाब से 9 रुपए अधिक है।

- पंजाब की आढ़ती एसोसिएशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, पंजाब सरकार की नीतियों पर जताई चिंता
- प्रदेश के किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं: नायब सैनी
- गेहूं पर आढ़तियों को प्रति क्विंटल दे रहे हैं पंजाब से 9 रुपये अधिक कमीशन

आढ़ती एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो उनकी बात सुने और ठोस समाधान दे। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वालों में आढ़ती पंजाब फेडरेशन के अध्यक्ष विजय कालरा, पंजाब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह बराड़, पंजाब के उपाध्यक्ष देवी दयाल, आढ़ती एसोसिएशन पटियाला के अध्यक्ष मुल्ख राज गुप्ता, मोगा के अध्यक्ष समीर जैन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की आत्मीय मेहमाननवाजी और दिए गए ठोस आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया। बैठक में पंजाब भाजपा संगठन मंत्री श्री निवासुलु मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन तथा श्री बी.बी भारती भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईजीएमसी में किया न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन

प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में पहली बार 'पैट स्कैन' सुविधा शुरू

स्पैक्ट-सीटी मशीन के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पैट) स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

पैट स्कैन सुविधा रोगों का प्रारंभिक स्तर पर, मेटाबॉलिक और मॉलिक्यूलर स्तर पर पता लगाने में सक्षम है। पारंपरिक इमेजिंग तकनीकों जैसे सीटी और एमआरआई की तुलना में, जो बाद के चरणों में संरचनात्मक बदलाव दिखाती हैं, पैट तकनीक बहुत पहले ही शारीरिक परिवर्तनों का पता लगा लेती है। यह सुविधा कैंसर के स्टेज निर्धारण और पुनः मूल्यांकन, उपचार के प्रभाव का आकलन, बीमारी की पुनरावृत्ति का पता लगाने और रोग के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह तकनीक मस्तिष्क ट्यूमर, सिर और गर्दन के कैंसर, थायरॉयड कारसिनोमा, लंग्स कारसिनोमा, मैलिगनेंसिज, थाइमिक इसोफेगोगेसट्रिक कारसिनोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ब्रेस्ट कारसिनोमा, कोलोरेक्टल कारसिनोमा तथा यूरोलॉजिकल एवं टेस्टिकूलर मैलिगनेंसिज के निदान और प्रबंधन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। नई तकनीकों और ट्रेसर के विकास के साथ, ऑन्कोलॉजी में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऑन्कोलॉजी के अलावा, पैट स्कैन का उपयोग अब हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, संक्रमण और सूजन संबंधी रोगों के आकलन में भी किया जा रहा है, विशेषकर उन मामलों में जहां पारंपरिक इमेजिंग से स्पष्ट निष्कर्ष नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इस प्रमुख संस्थान में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का भी शुभारम्भ किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में तकनीकी उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सुलभ और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में स्पैक्ट-सीटी स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 8 करोड़ रुपये की भी घोषणा की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा व संजय अवस्थी, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हनुमान जन्मोत्सव पर संकटमोचन के दर पहुंचे सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर

मंत्री विक्रमादित्य ने भी टेका मत्था

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी पत्नियों के संग भगवान हनुमान के चरणों में शीश नवाया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से इतर, भक्ति के इस माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज एक ही छत के नीचे आशीर्वाद लेते नजर आए।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह जाखू मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा आज हनुमान जयंती का पवित्र दिन है। हम संकटमोचन हनुमान जी से प्रेरणा लेने और मत्था टेकने आए हैं। बजरंगबली हमें शक्ति दें कि हम प्रदेश की जनता की निस्वार्थ सेवा कर सकें।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी परिवार सहित मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा हनुमान जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रभु हम सबकी रक्षा करें, सबको शक्ति दें और हिमाचल को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का बल प्रदान करें। जाखू में भक्तों का उत्साह देखकर मन प्रसन्न है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस अवसर पर जाखू पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु राम और हनुमान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे ताकि हिमाचल प्रदेश हर संकट से बाहर निकल सके और यहाँ खुशहाली का वास हो। हनुमान जन्मोत्सव के चलते जाखू मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। भारी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के दर्शन किए और आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।

शिमला में इस साल की सबसे बड़ी 288 ग्राम चिट्टा बरामदगी, एक गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 मार्च को शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए आईएसबीटी शिमला क्षेत्र में गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कैरी बैग में भारी मात्रा में चिट्टा लेकर आईएसबीटी के प्रथम तल पर घूम रहा है और स्थानीय युवाओं को बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए हुलिये के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की। उसकी पहचान शमशाद अहमद (42 वर्ष), निवासी जिला अंबाला, हरियाणा के रूप में हुई। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में उसके कैरी बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से 288 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे 25 मार्च को अदालत में पेश किया। अदालत से आरोपी को छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिससे मामले की गहराई से जांच की जा सके। गौरव सिंह के अनुसार मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी यह मादक पदार्थ कहां से लेकर आया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाने की योजना थी।

शिमला से लापता नाबालिग बालिका कालका से सकुशल बरामद

शिमला। जिला शिमला में नाबालिग बालिका के लापता होने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार बालिका अपने परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से चली गई थी और कालका क्षेत्र में अपने एक दोस्त के घर पहुंच गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत थाना महिला शिमला में दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसी दिन भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया और बालिका की तलाश के लिए तुरंत विशेष टीम गठित की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत तलाश अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी का उपयोग करते हुए लगातार प्रयास जारी रखे। पुलिस की इसी सक्रियता के चलते अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल 2026 को बालिका को कालका क्षेत्र में काली माता मंदिर मुख्य मार्ग के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि बालिका घर में परिजनों की डांट से नाराज होकर बिना बताए कालका चली गई थी और वहां अपने एक परिचित के घर ठहरी हुई थी।

शाहपुर कंडी बांधः पंजाब के साथ 1979 के समझौते पर अडिग उमर अब्दुल्ला, बोले- 'यह सरकारों की संप्रभु प्रतिबद्धता'

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधानसभा के पटल से पड़ोसी राज्य पंजाब को दशकों पुराने जल समझौते की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह शाहपुर कंडी बांध परियोजना के संबंध में जम्मू-कश्मीर के हक और पंजाब सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे।

उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि दो राज्यों के बीच हुए एक ऐतिहासिक और कानूनी समझौते का है, जिसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने शाहपुर कंडी बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकार के बीच साल 1979 में जो समझौता हुआ था, वह दो सरकारों के बीच एक 'संप्रभु प्रतिबद्धता' है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वह इस मामले को अपने स्तर पर पंजाब के अपने समकक्ष के साथ उठाएंगे।

यह कोई व्यक्तिगत वादा नहीं है जिसे भुला दिया जाए। यह पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सरकारों के बीच का आधिकारिक अनुबंध है। समझौते से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं उन्हें (पंजाब सीएम) याद दिलाऊंगा और इस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए मनाऊंगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना का निर्माण पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से जम्मू-कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलना है। दशकों से लंबित इस परियोजना के कारण जम्मू-कश्मीर अपने हिस्से के पानी का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि वह टकराव के बजाय कूटनीतिक और दोस्ताना बातचीत के जरिए इस पुराने विवाद को सुलझाना चाहते हैं। विधानसभा में उनके इस कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि वर्तमान सरकार केंद्र शासित प्रदेश के संसाधनों और कानूनी अधिकारों को लेकर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है।

संक्षिप्त-समाचार

स्कूल वैन दुर्घटना में चालक की मौत, दो घायल

जम्मू। गुरुवार को श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटा घर के पास एक स्कूल वैन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। सौभाग्य से छात्र इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। अधिकारियों ने बताया कि चालक जिसकी पहचान उमैर आबाद बेमिना के निवासी 47 वर्षीय जावेद अहमद के रूप में हुई है जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे तुरंत एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जावेद अहमद स्कूल वैन चला रहा था जब एसएसआई बैंक लाल चौक के सामने उसका नियंत्रण बिगड़ गया जिसके परिणामस्वरूप उसे कई गंभीर चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि तमाम प्रयासों के बावजूद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना में दो अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

सड़क विस्तार के लिए वन मंजूरी अनिवार्यः उपमुख्यमंत्री

जम्मू। जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती यातायात समस्याओं से निपटने और सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंजूरी और बुनियादी ढांचे का उन्नयन अनिवार्य है। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा को सूचित किया कि प्रस्तावित सड़क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वन भूमि में आता है इसलिए परियोजना के क्रियान्वयन से पहले वन मंजूरी अनिवार्य है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 5.5 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क बढ़ते यातायात भार को संभालने के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही में वृद्धि, विशेष रूप से लस्सीपोरा में औद्योगिक विकास केंद्र के कारण सड़क बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा रही है। उन्होंने क्षेत्र में सुगम यातायात प्रवाह और बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया।

उपराज्यपाल ने पुनर्वास योजना के तहत बलिदानी सब-इंस्पेक्टर की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा

जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को बलिदानी सब-इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की पत्नी श्रीमती अलका शर्मा को जम्मू और कश्मीर पुनर्वास सहायता योजना, 2022 के तहत नियुक्ति पत्र सौंपा। उपराज्यपाल ने शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन भी दिया। उपराज्यपाल ने शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के इस बहादुर जवान ने 2024 में कठुआ में एक सबसे वांछित गैंगस्टर से बहादुरी से लड़ते हुए और उसे मार गिराते हुए कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान दिया था।

पीडीपी विधायक ने सीएम उमर की सराहना की, प्रमुख विधेयक पर समर्थन मांगा

जम्मू। त्राल से पीडीपी विधायक रफीक अहमद नाइक ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रशंसा की जबकि राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण कानून पर मतभेदों से ऊपर उठने का आग्रह किया। कार्यवाही के दौरान बोलते हुए नाइक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता के सामने आने वाले कई मुद्दों को हल करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने सरकार की जवाबदेही के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद ऐसे प्रयास सराहना के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि वह समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए अपने मतदाताओं की चिंताओं को उठाना जारी रखेंगे, उन्होंने कहा कि सराहना जवाबदेही की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मंत्री सकीना इटू द्वारा पेश किए गए एक विधेयक का जिक्र करते हुए विधायक ने इसे महत्वपूर्ण बताया और पार्टी लाइनों से परे सदस्यों से इसका समर्थन करने का आान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण कानून को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्थक विधेयकों का विरोध नकारात्मक संकेत भेजता है और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को कमजोर करता है।

हिमाचल में विकास की डबल डोजः 17 लाख परिवारों को मिला नल से जल और 82 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

मोदी सरकार ने हिमाचल में 17 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचाया स्वच्छ पानीः सुरेश कश्यप

शिमला। भाजपा के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में हुए ऐतिहासिक कार्यों को लेकर केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प तेजी से पूरा हो रहा है। सांसद कश्यप ने लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन (खखट) की शुरूआत अगस्त 2019 में हुई थी, उस समय देश में केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध था। लेकिन मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़कर 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 17.08 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत न केवल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बल्कि नियमित जल आपूर्ति, गुणवत्ता नियंत्रण और दीर्घकालिक स्थायित्व पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निरंतर तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

जम्मू कोर्ट बना अखाड़ाः पेशी पर आए आरोपियों पर जानलेवा हमला, पिस्टल लहराने से वकीलों में दहशत

धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपियों पर जानीपुर अदालत में धावा

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू के जानीपुर स्थित अदालत परिसर में बुधवार सुबह उस वक्त युद्ध जैसी स्थिति बन गई, जब धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपियों पर पेशी के दौरान हमला कर दिया गया। हमलावरों और वकीलों के बीच जमकर टकराव हुआ, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। घटना के दौरान एक हमलावर द्वारा पिस्टल लहराने की बात भी सामने आई है, जिसने न्यायिक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला 7 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी और युवा राजपूत सभा के दिलावर सिंह की शिकायतों पर चार आरोपियों– मोहम्मद आरिफ, शाहिद, यूनुस और इमरान–के खिलाफ सतवारी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इन्होंने वीडियो के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी। आरोपी फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं और बुधवार सुबह स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ज्योति भगत की अदालत में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। जैसे ही आरोपी कोर्ट परिसर में दाखिल हुए, कार में सवार होकर आए कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। बचाव में आए वकीलों के साथ भी हमलावरों की तीखी नोकझोंक और हाथापाई हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों में से एक के पास पिस्टल थी, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही जानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि, अधिकांश हमलावर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने सरफराज नामक एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सरफराज रियासी के पौनी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। जानीपुर थाना प्रभारी (रलड) विक्रम शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने वकीलों और जजों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस 'सुरक्षा चूक' पर कड़ा ऐतराज जताया है। निर्मल कोतवाल, अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जम्मू ने कहा यह सुरक्षा में बड़ी सेंध है। हम बार-बार वकीलों और जजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में लगे कैमरे सभी हिस्सों को कवर नहीं करते। सरकार को तुरंत पुख्ता कदम उठाने चाहिए।

जम्मू-कश्मीर को मिलेगी सिर्फ 12% बिजलीः पारा

जम्मू। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद उर रहमान पारा ने गुरुवार को खुलासा किया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने दो नई जलविद्युत परियोजनाएं - 240 मेगावाट की उड़ी स्टेज-ककक और 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज-ककक परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 500 मेगावाट है राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) को सौंप दी हैं। यह समझौता एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर जलविद्युत निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच इस वर्ष 27 मार्च को हस्ताक्षरित हुआ था। पीडीपी विधायक के अनुसार समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत जम्मू-कश्मीर एनएचपीसी द्वारा संचालित परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का 12 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पाने का हकदार है। उन्होंने कहा कि शेष बिजली बिजली ग्रिड को हस्तांतरित की जाएगी जिससे जम्मू-कश्मीर सरकार ऊर्जा घाटे को पूरा करने के लिए बाजार दरों पर बिजली खरीदती है। पीडीपी विधायक ने कहा कि इन परियोजनाओं को 40 वर्षों तक बूट ओट मॉडल के तहत कार्यान्वित किया जाएगा जिसके बाद इन्हें केंद्र शासित प्रदेश को वापस सौंप दिया जाएगा। पारा ने यह बात एक्स पर एक पोस्ट में लिखी। उन्होंने कहा कि 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास पर कार्य समूहों का गठन किया था।

अधिकारियों की आपसी जंग में बेबस हैं मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार का बजट दूरदर्शिता से कोसों दूरः जयराम

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

विधानसभा सत्र के समापन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने का बजट तथ्य दूरदर्शिता और विकास से कोसों दूर है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में गत वर्ष की अपेक्षा बजट में कमी आई है। सरकार द्वारा लगातार अपनी नाकामी का दोष केंद्र को दिया जा रहा है लेकिन हकीकत यह है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को भाजपा सरकार के मुकाबले ज्यादा धनराशि दी जा रही है। चिट्टा शराब खनन वन माफिया तांडव मचा रहा है। पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल की रहे है। साजिशें कर रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी कोशिश नाकाम हो गई जिसके बाद चुनाव करवाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में चार दिन से प्रदर्शन हो रहा है। एक छात्र ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या की है और सरकार कार्रवाई करना तो दूर जानकारी लेने और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में जो हालात बने हैं वह बहुत चिंताजनक, गंभीर और शर्मनाक है। सीएम सब जानने के बाद कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हमने विधान सभा में मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन सीएम चुप हैं। संदिग्ध अधिकारियों को प्राइम पोस्टिंग दी गई हैं। उनकी हजार शिकायते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करना तो दूर मुख्यमंत्री कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 2 चरणों में की जाएगी जनगणना : सीपीसीओ अमित शर्मा

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में सटीक और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित करने के लिए स्व-गणना, मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह और जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल बैकबोन में दो चरणों में जनगणना की जाएगी।

मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अभ्यास पारंपरिक तरीकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें प्रौद्योगिकी गणना से लेकर डेटा प्रोसेसिंग तक केंद्रीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जनशक्ति की तैनाती होगी, जिसमें हजारों पर्यवेक्षकों और गणनाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी और एक मजबूत डिजिटल ढांचे का लाभ उठाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिकों के पास एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं-गणना का विकल्प भी होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक समावेशी और कुशल हो जाएगी। स्व-गणना सुविधा व्यक्तियों को अपना विवरण ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगी, जिससे क्षेत्र का कार्यभार कम होगा और वास्तविक समय डेटा सत्यापन सक्षम होगा। शर्मा ने कहा कि घरों की सूची और गणना के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लांच किए जाएंगे, जबकि गणना ब्लॉकों को सटीक रूप से मैप करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस टूल का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेटा कैप्चर से लेकर भंडारण तक प्रौद्योगिकी एकीकरण से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। सुरक्षित डेटा केंद्र विश्वसनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए प्रसंस्करण को संभालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक विश्वास बनाने और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों सहित वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों से स्व-गणना में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मौसम **हिमाचल में अगले 6 दिन भारी; आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी**

8 अप्रैल तक बरसेंगे बादल, आंधी-ओलावृष्टि का अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 अप्रैल तक बादल छाए रहने, कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। विभाग ने इस अवधि के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य 10 जिलों में आंधी चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इन दो दिनों के लिए कई क्षेत्रों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है और इन दिनों के लिए भी आंधी और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, खासतौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों भी इन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी और ठंड का असर बढ़ गया था। यदि इस विंटर सीजन की बात करें तो दिसंबर और जनवरी का अधिकतर समय सूखा रहा था। 22 जनवरी को सीजन की पहली भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन इसके बाद फरवरी में भी अपेक्षाकृत कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। मार्च का आधा महीना भी सूखा रहा, हालांकि 18 मार्च के बाद मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इस बीच शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में 11.6 डिग्री, सुंदरनगर में 13.1 डिग्री, भुंतर में 11.5 डिग्री, कल्पा में 5 डिग्री, धर्मशाला में 6.5 डिग्री, उना में 15.4 डिग्री, नाहन में 14.5 डिग्री, सोलन में 12 डिग्री और मनाली में 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों और यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्योन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा में ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वे, मुख्य सचिव ने दिया समयबद्ध सर्वेक्षण पर जोर

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने ज्ञान भारतम पहल के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज यहां उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ज्ञान भारतम पहल के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा कर रहे थे। श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दशार्ता है, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा के संरक्षण, नवाचार और अनुकूलन को प्रमुख स्तंभ माना गया है। सितंबर 2025 में शुरू किया गया ज्ञान भारतम पोर्टल आधुनिक तकनीक की मदद से सदियों पुरानी पांडुलिपियों की पहचान और संरक्षण के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

श्री रस्तोगी ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि हर जिले में व्यवस्थित और समयबद्ध सर्वे सुनिश्चित किया जाए। इस सर्वे में संस्थानों के साथ-साथ मंदिरों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकताओं के पास उपलब्ध पांडुलिपियों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए उचित दस्तावेजीकरण, सूचीकरण और मानकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना आवश्यक है। कार्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वेक्षण एक संरचित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसमें पांडुलिपियों और संरक्षकों की पहचान, भौतिक सत्यापन एवं स्थिति का आकलन, विस्तृत सूचीकरण और मेटाडाटा तैयार करना, संरक्षण एवं उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटाइजेशन तथा अंत में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए रिपॉजिटरी स्तर पर सत्यापन शामिल होगा।

तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय स्कैनर, मेटाडाटा निर्माण और क्लाउड स्टोरेज के साथ सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी में डिजिटाइज्ड पांडुलिपियों को अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन ग्रंथों को अधिक सुलभ बनाने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और हैंडरिटन टेक्स्ट रिकग्निशन जैसी उन्नत तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। क्षमता निर्माण के महत्व पर बल देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि संरक्षण कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्राचीन लिपियों में विशेष प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की निगरानी में तथा जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने प्रगति की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए नियमित और पखवाड़ा समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जून माह तक फील्ड सर्वे पूरा किया जाए। इसके लिए पूर्व-सर्वे समन्वय और निरंतर निगरानी की व्यवस्था की जाए। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों, मीडिया विज्ञापनों तथा विशेषज्ञ नेटवर्क के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेख दान अभियान और धरोहरशास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसी पहलों की भी समीक्षा की। श्री रस्तोगी ने कहा कि इस पहल से व्यापक पांडुलिपि डेटाबेस तैयार होगा, दुर्लभ और लुप्तप्राय पांडुलिपियों की पहचान होगी, जीआईएस आधारित राष्ट्रीय रिपॉजिटरी विकसित होगी और भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संरक्षण में संस्थागत और सामुदायिक भागीदारी मजबूत होगी। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए, जबकि अभिलेखागार विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, निदेशक डॉ. बलप्रीत सिंह, उपनिदेशक अभिलेखागार मंजू यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा में स्वास्थ्य संस्थानों में पानी के टैंकों की तत्काल सफाई के दिए आदेश: डॉ. सुमिता मिश्रा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य भर के सरकारी मेडिकल संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी के सभी टैंकों की तत्काल जाँच और सफाई के लिए सख़्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति पर बल दिया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि समय-समय पर संज्ञान में आया है कि कई संस्थानों में पानी के टैंकों की नियमित रूप से सफाई नहीं की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

उन्होंने सभी संस्थानों को निर्देश दिए गये है कि वे जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे बने, दोनों तरह के पानी के टैंकों की तत्काल और पूरी तरह से जाँच करें। इस जाँच में टैंकों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह के प्रदूषण, रिसाव या ढाँचे को हुए नुकसान के संकेतो की पहचान करना भी शामिल है, ताकि संभावित खतरों को रोका जा सके। जारी निदेर्शों के तहत सभी टैंकों की पूरी तरह से सफाई करना अनिवार्य है। इसमें टैंकों में जमा गाद को हटाना, अंदर की सतहों को ठीक से धोना और निर्धारित सुरक्षा व स्वच्छता मानकों के अनुसार कीटाणु-मुक्त करना शामिल है। संस्थानों को निर्देश दिये गये है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह पूरी प्रक्रिया केवल अनुमोदित (मंजूर) तरीकों का उपयोग करके ही की जाए।

डॉ. मिश्रा ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे पानी के टैंकों की समय-समय पर जाँच और सफाई के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तय करें, जिसे प्राथमिकता के आधार पर हर तीन महीने (त्रैमासिक) में लागू किया जाए और किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोका जाए। इसका उद्देश्य पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को लगातार बनाए रखना है। सभी संबंधित अधिकारियों को इन निदेर्शों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और 5 अप्रैल, 2026 तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट (पालन की रिपोर्ट) जमा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उपायुक्तों को निर्देश दिये गये है कि वे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से इन निदेर्शों के कार्यान्वयन की निगरानी करें और सात दिनों के भीतर अपनी निगरानी रिपोर्ट जमा करें।

डॉ. मिश्रा ने पुनः दोहराया कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुँचाना स्वास्थ्य सेवा वितरण का एक बुनियादी और अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि हरियाणा भर के स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में किसी भी तरह की कोई चूक न हो।

कुरुक्षेत्र में एलपीजी गैस सिलेंडर व पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सामान्य : नरेश कुमार

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

3 कंपनियों की 27 गैस एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार ने कहा कि जिला में एलपीजी गैस सिलेंडर व पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार ने कहा कि गैस की कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष टीम का गठन किया हुआ है। इन टीम द्वारा जिलेभर में होटलों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों व ढाबों पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग न हो सके। जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह संतुलित है। विभिन्न तेल कंपनियों से प्राप्त सप्लाई और एजेंसियों के पास उपलब्ध स्टॉक के माध्यम से उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार ने कहा कि जिला में कार्यरत 3 कंपनियों की 27 गैस एजेंसियों हैं। जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध हैं। सभी गैस एजेंसियों जिले में द्वारा कुल 9528 रिफिल किये गये। जिले में प्रतिदिन उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार तीनों तेल कंपनियों द्वारा घरेलू गैस की पूर्ति की जा रही है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेश कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बुकिंग व्यवस्था को और सरल बनाया गया है। नागरिक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से गैस बुक कर ओटीपी के माध्यम से सुरक्षित तरीके से सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।

कुरुक्षेत्र में आज होगा 18वां गोयल पुरस्कार समारोह, देश के शीर्ष वैज्ञानिक होंगे सम्मानित

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज विज्ञान के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित आयोजन 18वां गोयल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में प्रातः 10.30 बजे आयोजित होने वाले इस समारोह में देश के प्रमुख वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध, नवाचार और विज्ञान में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस गरिमामयी समारोह में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के. सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा करेंगे।

कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि वर्ष 1992 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार प्रदान करता आ रहा है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस वर्ष समारोह में वर्ष 2023-24 के लिए 04 गोयल पुरस्कार और 04 राजीब गोयल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति की संयोजक प्रो. अनीता भटनागर ने बताया कि गोयल पुरस्कार के अंतर्गत एप्लाइड साइंसेज में डॉ. अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित, केमिकल साइंसेज में डॉ. थालप्पिल प्रदीप, लाइफ साइंसेज में डॉ. परमजीत खुराना तथा फिजिकल साइंसेज में डॉ. श्रीराम रामास्वामी को सम्मानित किया जाएगा। इन वैज्ञानिकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान देकर शोध के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 2 लाख रुपये की नकद राशि, स्वर्ण पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 45 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को राजीब गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अंतर्गत एप्लाइड साइंसेज में डॉ. गोपीनाथ पैकिरिसामी, केमिकल साइंसेज में डॉ. देबब्रत मैती, लाइफ साइंसेज में डॉ. दुर्गा पाल तथा फिजिकल साइंसेज में डॉ. स्मराजीत कर्माकर को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रशस्ति-पत्र तथा एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। प्रो. अनीता भटनागर ने बताया कि गोयल पुरस्कार देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में से एक है, जो वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रेरित करता है।

समारोह के सह-संयोजक प्रो. एस.पी. सिंह तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. वीरेंद्र पाल आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि इस अवसर पर सम्मानित वैज्ञानिकों के शोध कार्यों और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा।

संक्षिप्त-समाचार

पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कृषि वैज्ञानिक डा. सीबी सिंह को किया सम्मानित

कुरुक्षेत्र। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त एवं करीब 6 दशकों से किसानों की सेवा कर रहे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. सीबी सिंह को पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र में सम्मानित किया। इस मौके पर उन्हें विशेष तौर पर सब्जियों की खेती पर अनुसंधान एवं आधुनिक कृषि विधियों पर किए कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। सुभाष सुधा ने डा. सीबी सिंह को सम्मानित करने के बाद कहा कि डा. सिंह आज भी किसानों के लिए विशेष कृषि मार्गदर्शन व अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा आलू की नई किस्में उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य प्रदेशों तक भी पहुंची हैं। इस मौके पर डा. विजय नाथ सिंह, डा. बृजेश, मंगलकरण, गोपिका, मनीषा इत्यादि भी मौजूद रहे।

जिला पुलिस के 4 निरीक्षक पदोन्नत, पुलिस अधीक्षक ने स्टार लगाकर दी शुभकामनाएं

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पुलिस से 4 उप निरीक्षक हुए निरीक्षक पदोन्नत। जिला पुलिस के उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, जगपाल, करण सिंह व कृष्ण कुमार पदोन्नति पाकर निरीक्षक बने हैं। पदोन्नत निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार को पुलिस अधीक्षक ने स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय व पुलिस महानिरीक्षक अमबाला मंडला अम्बाला से प्राप्त आदेशों की पालना करते हुए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री चन्द्र मोहन ने सुरेन्द्र कुमार को स्टार लगाकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सभी निरीक्षक हरियाणा पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती हुए तथा मेहनत, लग्न व ईमानदारी से अपनी डयूटी करते हुए निरीक्षक पद तक पहुंचे हैं। सभी निरीक्षक जिला कुरुक्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नत कर्मचारियों को प्रमोशन की बधाई देते हुए कहा की अब उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं, इसलिए अपने पद की गरिमा बनाए रखें तथा और ज्यादा मेहनत करते हुए ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पुराना व क्षतिग्रस्त तिरंगा, सौंपने रादौर का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कुरुक्षेत्र

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

सांसद नवीन जिन्दल के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान को मिल रहा है जनसमर्थन

राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के उद्देश्य से सांसद नवीन जिन्दल द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियानझ2026 को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में व्यापक जनसहभागिता मिल रही है। इसी क्रम में आज रादौर से एक प्रतिनिधिमंडल जिन्दल हाउस, कुरुक्षेत्र पहुंचा और अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में महाराणा प्रताप पार्क एसोसिएशन के प्रधान भारत माटिया, देवी दयाल अरोड़ा, मोहनलाल अरोड़ा, मलखान सिंह और जसवंत सिंह शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य महाराणा प्रताप पार्क में स्थापित पुराने एवं क्षतिग्रस्त तिरंगे को पुनः नवीनीकरण हेतु सौंपना था।

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से भूषण मंगला, डॉ. राज कुमार तथा राजिंद्र राजपूत ने तिरंगा प्राप्त किया और इसे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत पुनः नवीनीकरण के लिए स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस अभियान के अंतर्गत पूरे संसदीय क्षेत्र से पुराने, मैले और क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वजों को एकत्रित किया जा रहा है। इस कार्य में सामाजिक संस्थाएं, संगठन और आम नागरिक भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभियान का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखना है, बल्कि नागरिकों में इसके प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। इस अवसर पर भारत माटिया ने कहा कि रादौर के महाराणा प्रताप पार्क में स्थापित विशाल तिरंगा सांसद नवीन जिन्दल द्वारा क्षेत्रवासियों को दिया गया एक अनमोल उपहार है, जिसकी देखरेख पार्क एसोसिएशन द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि समय के साथ ध्वज के क्षतिग्रस्त होने पर उसे सम्मानपूर्वक बदलना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सांसद नवीन जिन्दल की इस प्रेरणादायक पहल से प्रेरित होकर ही वे यह तिरंगा सौंपने के लिए यहां पहुंचे हैं, ताकि इसका विधिवत पुनःनवीनीकरण किया जा सके और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद कार्यालय प्रभारी एवं पूर्व आईएएस अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह अभियान समाज में राष्ट्रभक्ति और सम्मान की भावना को मजबूत कर रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने आसपास लगे पुराने या क्षतिग्रस्त तिरंगों को अभियान के तहत जमा करवाएं, ताकि उनका सम्मानजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

आठ नई पीएचसी के लिए 37.60 करोड़ मंजूरः आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 8 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के निर्माण के लिए 37.60 करोड़ की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन नए पीएचसी के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह पीएचसी फतेहाबाद जिले के बनगांव और समैण, हिसार जिले के लाडवा, रोहतक जिले के गिरावड़ और समर गोपालपुर, सोनीपत जिले के फरमाणा और सरगथल तथा सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सिरसा जिले के मल्लेकन गांव में मौजूदा पीएचसी भवन को जर्जर और असुरक्षित घोषित किया जा चुका है, जिसके स्थान पर अब आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन बनाया जाएगा। वहीं अन्य गांवों में पहली बार पीएचसी भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके नजदीक ही मिल सकेंगी। वित्तीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए आरती सिंह राव ने कहा कि इस परियोजना के लिए 1144 लाख की राशि 15वें वित्त आयोग के तहत और 2616.72 लाख राज्य बजट हेड 4210 से खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार कुल परियोजना लागत 37.60 करोड़ आंकी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन पीएचसी के निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 18 से 24 महीने का समय लगेगा। परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए धनराशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन पीएचसी के शुरू होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि बड़े अस्पतालों पर भी दबाव कम होगा। इससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने, नई सुविधाएं जोड़ने और हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी राज्यों में सर्वाधिक सकल एसजीएसटी वृद्धि दर दर्ज की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करदाता आधार में 12% की हुई वृद्धि

हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) राजस्व की वृद्धि दर के आधार पर देश के सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसजीएसटी राजस्व में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 6 प्रतिशत ही है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने हरियाणा को भारत के सभी राज्यों में एसजीएसटी राजस्व वृद्धि में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। हरियाणा का सकल एसजीएसटी संग्रह (पोस्ट-सेटलमेंट) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,289 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संग्रह से 8,546 करोड़ रुपये अधिक है। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, सकल एसजीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) संग्रह के मामले में, हरियाणा वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9वें स्थान पर था।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 को हरियाणा में 6,30,818 पंजीकृत करदाता हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करदाता आधार में 12% की वृद्धि हुई है। जीएसटी के लागू होने के बाद के वर्षों में करदाताओं की संख्या में स्थिर वृद्धि दिखाई दी है। सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दरों में सुधारों के बाद, हरियाणा राज्य एसजीएसटी संग्रह में प्रशंसनीय वृद्धि दिखा रहा है, जो राज्य की उभरती अर्थव्यवस्था और डेटा विश्लेषण संचालित कर प्रशासन को दशार्ता है।

किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : कृषि मंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में आज विभागीय हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में हरियाणा बीज विकास निगम के वार्षिक लेबर टेंडर से संबंधित एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य बीज संसाधन, पैकिंग और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाना है, ताकि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस टेंडर की मंजूरी से बीज निगम की विभिन्न इकाइयों–हिसार, सिरसा, टोहाना, यमुनानगर, पटौदी और उमरी–में बीज उत्पादकों से रॉ बीज की समय पर खरीद सुनिश्चित होगी। इसके बाद बीजों का संसाधन, पैकेजिंग और प्रमाणीकरण भी तय समय सीमा में पूरा किया जा सकेगा। कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और किसानों की आय में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस टेंडर को मंजूरी देने से बीज निगम को लगभग 15 लाख रुपये की बचत होगी। यह निर्णय सरकार की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को भी दशार्ता है।

सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड रखेंगे सभी जिला नागरिक अस्पताल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सा अधिकारियों को सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं का रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए जिला नागरिक अस्पतालों में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर संचालित सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाओं के सुचारू संचालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। महानिदेशक के अनुसार, राज्य के जिला नागरिक अस्पतालों में वर्ष 2016 से सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हो रही हैं। इन सेवाओं का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद मरीज प्रतिदिन उठा रहे हैं। वर्तमान में ये सुविधाएं बीपीएल कार्ड धारकों, दिव्यांग भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एहर), लावारिस सड़क दुर्घटना पीड़ितों, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके आश्रितों तथा एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि इन सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित श्रेणी के किसी भी मरीज को जांच की सलाह दिए जाने पर उसका इंडोर एडमिशन या डे-केयर फाइल अवश्य बनाई जाए। साथ ही, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, लैब जांच, जांच की आवश्यकता, तथा मरीज की सहमति जैसी सभी जानकारी को उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा फाइल में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन इन जांचों से संबंधित आदेशों की जांच करें और संबंधित मेडिकल सुपरिटेंडेंट (टर) या प्रधान चिकित्सा अधिकारी (ढटड) द्वारा इनकी पुष्टि (काउंटरसाइन) सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को इन निदेर्शों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए इसे अत्यंत आवश्यक एवं तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

संपादकीय

62% की छलांग: 4.1 अरब डॉलर पार कर भारत बना रक्षा निर्यात का नया ग्लोबल खिलाड़ी !

भारत ने वित्त वर्ष के अंत तक रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 62 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जिससे निर्यात का कुल आंकड़ा लगभग 4.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि केवल आर्थिक वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रभाव के निरंतर विस्तार को भी दशार्ती है। लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल रहने वाला भारत अब तेजी से एक सशक्त रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस उल्लेखनीय वृद्धि के पीछे पिछले कुछ वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी है। रक्षा उत्पादन में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना और विदेशी निवेश के नियमों में ढील देना जैसे कदमों ने इस क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। इसके साथ ही, कई रक्षा उत्पादों को आयात प्रतिबंध सूची में शामिल कर घरेलू उद्योग को मजबूत आधार प्रदान किया गया है। भारत के रक्षा निर्यात की खासियत अब इसकी विविधता और तकनीकी उन्नति में दिखाई देती है। जहां पहले निर्यात सीमित और पारंपरिक उपकरणों तक केंद्रित था, वहीं अब इसमें उन्नत मिसाइल प्रणालियां, अत्याधुनिक रडार, निगरानी उपकरण, ड्रोन, संचार प्रणाली और आर्टिलरी गन जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पाद शामिल हो चुके हैं। इन उत्पादों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमत और गुणवत्ता ने भारत को एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। भारत का रक्षा निर्यात अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैल चुका है। कई विकासशील देशों के लिए भारत एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है, जो न केवल किफायती है, बल्कि राजनीतिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय भी है। इन देशों के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग समझौते, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने भारतीय उत्पादों के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। इससे नए बाजार खुल रहे हैं और भारत की वैश्विक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स की बढ़ती भागीदारी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहले जहां रक्षा उत्पादन मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक सीमित था, वहीं अब निजी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से निवेश कर रही हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, नवाचार को बढ़ावा मिला है और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। विशेष रूप से एम एस एम ईज और स्टार्टअप्स नई तकनीकों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे रक्षा उत्पादन का दायरा और मजबूत हो रहा है। भारत की रक्षा कूटनीति भी इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी, रक्षा समझौते और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने भारत की विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सक्रियता और सहयोगात्मक दृष्टिकोण ने उसे एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है। इससे रक्षा निर्यात को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला है। हालांकि, इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। वैश्विक रक्षा बाजार में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों का दबदबा बना हुआ है, जिनके पास अत्याधुनिक तकनीक और व्यापक बाजार नेटवर्क है। ऐसे में भारत को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करना होगा। तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा, निर्यात प्रक्रियाओं में जटिलता और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याएं भी एक बड़ी बाधा हैं। कई बार प्रशासनिक देरी और जटिल नियमों के कारण निर्यात प्रभावित होता है। यदि इन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाए, तो भारत अपने रक्षा निर्यात को और तेजी से बढ़ा सकता है। साथ ही, कुशल मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता का विकास भी इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी है। सरकार ने आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को 5 अरब डॉलर से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई और उभरती तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा और स्वदेशी हथियार प्रणालियों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, रक्षा औद्योगिक गलियारों और उत्पादन क्लस्टरों का विकास भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत अब केवल तैयार उत्पादों का निर्यात ही नहीं कर रहा, बल्कि तकनीकी सहयोग, संयुक्त उत्पादन और रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। इससे न केवल निर्यात का दायरा बढ़ेगा, बल्कि भारत की वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। समग्र रूप से देखा जाए तो भारत के रक्षा निर्यात में यह रिकॉर्ड वृद्धि एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह देश की आर्थिक मजबूती, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत अब केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रभावशाली खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान मिलकर इसी दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो आने वाले समय में भारत न केवल अपने निर्यात लक्ष्यों को पार कर सकता है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगी और उसे एक जिम्मेदार, सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी।

भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान

डॉ. रीना रवि मालपानी (हि.स)

राम नाम के अनन्य प्रेमी भक्त शिरोमणि अंजनीसुत हनुमानजी की महिमा से भला कौन परिचित नहीं है। रामायण की कल्पना रामदूत हनुमान के बिना नहीं की जा सकती। भक्त और भक्ति की उत्कृष्टता को सिद्ध करने वाले हनुमानजी की लीला न्यारी है। श्रीराम दूत हनुमान भक्ति की उच्च पराकाष्ठा को सिद्ध करते हैं, इसी कारण श्रीराम भी सदैव उनके साथ ही अपनी पूर्णता को प्रदर्शित करते हैं इसीलिए उन्हें भक्त शिरोमणि की भी संज्ञा दी गई है।

रामायण में हनुमानजी का नहीं श्रीराम दूत के नवीन रूप का अवतरण हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सेवा, भक्ति, कर्मों एवं प्रयासों से नवीन स्वरूप में संसार के समक्ष प्रत्यक्ष हो सकते हैं। महादेव के अंश रुद्रावतार ने श्रीराम के प्रति अनन्य भक्ति एवं प्रेम को हृदय में विराजमान किया। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है, यही गुण उनके रुद्रावतार हनुमानजी के स्वभाव में परिलक्षित होता है। वे भी प्रभु श्रीराम की प्रसन्नता के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर धारण करते हैं।

जहाँ धन, पद और यश के लालच में व्यक्ति अपना सुख-चैन, सर्वस्व त्याग देता है, वहीं हनुमानजी ने प्रभु श्रीराम के आग्रह पर उनके चरणपद ही माँग लिए और बाकी सबका सहज त्याग कर दिया।

हनुमानजी की अनूठी विशेषता उनका अहंकार शून्य होना भी है। हनुमानजी की प्रतिभा संपन्नता तो हमें बाल्य रूप से ही दिखाई देने लगती है। भूख लगने पर सूर्य को फल समझ कर खा लेना, उनकी अद्भुत शक्ति संपन्नता को प्रदर्शित करता है परंतु अपने सम्बोधन में वे रामदूत के उच्चारण को ही प्राथमिकता देते हैं। हनुमानजी में यदि सेवाभाव एवं पूर्ण समर्पण था तो श्रीराम भी हनुमान के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमानजी की एक और विलक्षण विशेषता यह है कि वे अपना परिचय सदैव श्रीराम के दूत के रूप में देते हैं।

हनुमानजी इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें ज्ञात है कि कब उन्हें लघु रूप धारण करना है और कब वृहद रूप धारण करके श्रीराम के कार्यों को शीघ्रता से सम्पन्न करना है। हमें सदैव अपने कार्य के प्रति उत्साह का भाव दिखाना चाहिए। जब श्रीराम के कार्य को पूरा करने के लिए हनुमान समुद्र पार करने गए तो वे अत्यंत उत्साहित थे और लक्ष्य के प्रति दृढ़निष्ठ थे। जब मैनाक पर्वत ने उन्हें रुकने को कहा तो उन्होंने कहा मुझे शीघ्रता से माता सीता का पता लगाना है और तत्परता से श्रीराम का कार्य करना है। कार्यों को प्राथमिकता देना भी हमें हनुमानजी से सीखना चाहिए।

श्रीराम दूत हनुमान के जीवन में भक्ति और शक्ति का अनूठा समन्वय दृष्टिगोचर होता है। रामायण का प्रत्येक चरित्र अद्भुत है परंतु रामायण के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्णता हनुमानजी ने दी। समुद्र लाँघना हो, माता सीता का पता लगाना हो, लंका दहन करना हो या लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करनी हो, यह सभी कार्य हनुमानजी के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुए; फिर भी वे प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय श्रीराम को देते हैं।

हनुमानजी के गुण स्वरूप कार्यों एवं आदर्शों के अनुरूप ही उनके बारह नाम है, जो मनुष्य को अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करते हैं। हनुमान, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुनसखा, पिङ्गाक्ष, अमितविक्रम, सीताशोकविनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीवदर्पहा इन सभी नामों को स्मरण करने से जीवन के पाप और संताप नष्ट होते हैं। कलयुग में हनुमान चालीसा और सुंदरकाण्ड तो हनुमानजी की कृपा प्राप्ति के लिए भक्तो के अमोघ शस्त्र है। हनुमान चालीसा की उत्कृष्टता तो इस बात में निहित है कि स्वयं गौरी के ईश महादेव उसके साक्षी बनते हैं। हनुमान चालीसा भी हममें अदम्य शक्ति, साहस, भक्ति एवं ऊर्जा का अंकुरण करती है।

श्रीरामकथा श्रवण के प्रेमी हनुमानजी सदैव श्रीराम के नाम स्वरूप एवं गुणों का दर्शन करते हैं। यदि हम जीवन के उपवन में भक्ति एवं प्रसन्नता के प्रसून को पल्लवित और पुष्पित करना चाहते है तो असाध्य कार्य को भी साध्य करने वाले रामभक्त हनुमान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। अद्वितीय भक्ति की प्रतीक माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नव निधि का आशीष दिया है।

हनुमानजी की विलक्षण लीला हमें शिक्षा देती है कि व्यक्ति के जीवन में कर्म ही प्रधान होते हैं। उन्हीं कर्मो की वजह से हनुमानजी श्रीराम को भरत एवं लक्ष्मण के समान प्रिय हुए। हनुमानजी की आत्मा की सुंदरता तो माता जानकी और श्रीराम के उनके हृदय में विराजमान होने से है।

भक्त शिरोमणि हनुमान भगवान और भक्ति सबकुछ प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। संसार के प्रत्येक दुर्गम कार्य को सुगमता से करने की क्षमता हनुमानजी में है। श्रीराम दूत के सम्बोधन से तो वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। स्वयं उत्तम चरित्र से शोभायमान हनुमानजी हमेशा श्रीराम के चरित्र को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। समस्त सद्गुणों के स्वामी हनुमानजी संकट मोचक हैं।

हनुमान जन्मोत्सव जैसे उत्सव हममें भक्ति की अनूठी ऊर्जा का संचार करते हैं।

अक्सर सांसरिक मोहमाया से भगवान की स्मृति खो देते हैं, परंतु प्रत्येक उत्सव हममें भगवान की स्मृति को जीवंत करता है। महाभारत में जब कुंती ने श्रीकृष्ण से दुःख मांगा तब श्रीकृष्ण ने कहा कि आपका पूरा जीवन अथक संघर्षों में व्यतीत हुआ इसके पश्चात भी आप दुःख माँग रही है। तब उन्होंने गोविंद को उत्तर दिया कि दुःख में सदैव आपकी स्मृति बनी रहती है। इसी प्रकार यह छोटे-छोटे उत्सव हमें भगवान के नाम रूपी बैंक में निवेश करने को प्रेरित करते है, जो मनुष्य योनि की सच्ची कमाई है।

तो आइये उन्हीं श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि हनुमानजी के जन्मोत्सव को पूर्ण हर्षोल्लास से मनाएं। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। प्रभु कभी भी पूजा के मापदंड एवं भक्ति के क्रियाकलाप नहीं देखते। राम कीर्तन भी हनुमानजी को अत्यंत प्रिय है। चारों युग में अपनी कीर्ति को प्रतिष्ठित करने वाले हनुमानजी कलयुग में रामकथा होने पर यत्र-तत्र विराजमान होते हैं, तो हम श्रीराम नाम के उद्घोष के साथ सहज ही रामभक्त हनुमान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

देश के सर्वोच्च सदन में उठती समान शिक्षा की पुकार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारत का संविधान अपने मूल में एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हों और वह अपने सामर्थ्य के अनुरूप विकास कर सके। यह विचार कहना होगा कि एक संवैधानिक संकल्प है जिसे अनुच्छेद 14, 21क और अन्य प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किया गया है, किंतु जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इस समानता की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं तब एक जटिल और विरोधाभासी परिदृश्य सामने उभरकर आता है।

वस्तुतः राज्यसभा में दिनेश शर्मा द्वारा उठाया गया प्रश्न इस विरोधाभास को और अधिक स्पष्ट करता है जिसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त संरचनात्मक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका यह तर्क कि 'संविधान की समानता की भावना के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव मौजूद है !' भले ही ये कहना किसी राजनेता का हो, किंतु यह वक्तव्य भारत की हकीकत है, जोकि आज एक गहन संवैधानिक विमर्श का विषय है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। यह संशोधन इस बात का प्रतीक था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ समानता और विशेषाधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है।

राज्यसभा में प्रस्तुत विचारों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों से छूट प्राप्त है जबकि अन्य संस्थानों को इन नियमों का पूर्णतः पालन करना होता है। दिनेश शर्मा ने इस स्थिति को अनुच्छेद 14 के साथ असंगत बताया और यह तर्क दिया कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की संरचनात्मक असमानता उत्पन्न होती है। यहां समझ लें कि यह प्रश्न प्रशासनिक अथवा कानूनी नहीं है, यह उस मूलभूत विचार से जुड़ा है कि क्या राज्य सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है ?

इस संदर्भ में अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्रदान कर एक तरह से देश में शिक्षा के व्यावहारिक स्तर पर एक असमान ढाँचे को भी वैधता प्रदान कर दी गई है। देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में यह असमानता कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं है, यह संरचनात्मक और व्यावहारिक रूप में भी स्पष्ट दिखाई देती है। भारत में सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और धार्मिक शिक्षण संस्थान इन सभी की गुणवत्ता संसाधन और अवसरों में भारी अंतर है। एक ओर महानगरों के निजी विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं और वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है। इस असमानता का परिणाम यह है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्र एक ही प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं किंतु उनकी तैयारी और अवसर समान नहीं होते।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में समानता सुनिश्चित किए बिना बाल अधिकारों की वास्तविक रक्षा संभव नहीं है। आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'समान शिक्षा प्रणाली ही सामाजिक न्याय की आधारशिला बन सकती है।' वस्तुतः यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा में असमानता सिर्फ शैक्षणिक समस्या तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है।

भारतीय चिंतन परंपरा में भी शिक्षा को समानता का माध्यम माना गया है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक 'एजुकेशन पॉलिटिक्स एंड वॉर' में लिखा है, 'शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानार्जन नहीं है, इससे समाज में नैतिक और सामाजिक संतुलन स्थापित करना है।' इसी प्रकार महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में यह विचार व्यक्त किया कि 'समान शिक्षा के बिना सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है।' इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा को व्यक्तिगत विकास का साधन होने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी माना गया है।

समान शिक्षा की आवश्यकता को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से यह जाति वर्ग और धर्म आधारित विभाजनों को कम कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह सभी को समान अवसर प्रदान कर प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बना सकती है। राजनीतिक दृष्टि से यह लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्योंकि शिक्षित और जागरूक नागरिक ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं। वैचारिक दृष्टि से यह समाज में एकरूपता और समरसता को बढ़ावा दे सकती है। यह भी सच है कि समान शिक्षा लागू करने में अनेक चुनौतियाँ भी हैं। क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या भाषाई और सांस्कृतिक विविधता राज्यों के अधिकार और निजी क्षेत्र की भूमिका ये सभी कारक इस प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। अतः समाधान का मार्ग संतुलन में निहित है जहाँ समानता और विविधता दोनों का सम्मान किया जाए।

वर्तमान समय में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने का प्रयास किया है। इस नीति में समानता, समावेशन और गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है। नीति के अंतर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा बहुभाषी शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की बात की गई है, किंतु इन नीतिगत प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर असमानता अभी भी बनी हुई है जिसका मुख्य कारण क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और संस्थागत विविधता है।

इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले सभी शिक्षण संस्थानों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाएँ जिनका पालन अनिवार्य हो। दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सभी संस्थानों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण हो सके। चौथा संसद और नीति निमार्ताओं को इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए ताकि शिक्षा को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठाया जा सके।

अतः यहां कहने का तात्पर्य यही है क हम सभी यह स्वीकारें कि समान शिक्षा एक नीतिगत लक्ष्य न होकर देश हित में एक नैतिक आवश्यकता है। जब तक भारत के प्रत्येक बच्चे को समान गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक संविधान में निहित समानता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी है कि 'शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं।' कहना होगा क यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था, इसलिए समय की मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए गंभीर और समन्वित प्रयास किए जाएँ। राज्यसभा में उठी यह बहस एक अवसर है, एक ऐसे भारत के निर्माण का जहाँ शिक्षा वास्तव में समान हो और हर नागरिक को अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। हम उम्मीद करें कि केंद्र एवं राज्य सरकारें इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगी।

आज का राशिफल

मेष: कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है। जमीन जायदाद का लाभ भी हो सकता है। श्रम साध्य कार्यों में सफल होंगे। भय तथा शत्रुहानि की आशंका रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: जमीन जायदाद का लाभ भी हो सकता है। श्रम साध्य कार्यों में सफल होंगे। आवासए मकान तथा वाहन की सुविधाएं मिलेंगी। कर्ज तथा रोगों से मुक्ति भी संभव है। नियोजित धन से लाभ होने लगेगा। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: कल का परिश्रम आज लाभ देगा। घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। बुद्धिए बल व पराक्रम सफल होगा। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। बुद्धिए बल व पराक्रम सफल होगा। व्यापार में वृद्धि व उत्तम लाभ मिलेगा। यार-दोस्तों के साथ सांझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: कल का परिश्रम आज लाभ देगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

तुला: राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। मेहमानों का आगमन होगा। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आय के अच्छे योग बनेगें। संतान की उन्नति के योग हैं। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते है। कोई प्रिय वस्तु या नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। सभाओं में मान-सम्मान बढ़ेगा। धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। माता पक्ष से विशेष लाभ। *(सिटी दर्पण)*

मकर: कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्रम बदलने होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। आय के स्त्रोत बनेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मीन: ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। अल्प-परिश्रम से ही लाभ होगा। *(सिटी दर्पण)*

धर्म, अंधविश्वास और अपराध: जिम्मेदारी तय करने का समय

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

भारतीय समाज में धर्म और आस्था की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। सदियों से लोग अपने जीवन के सुख-दुख, समस्याओं और अनिश्चितताओं के समाधान के लिए धार्मिक व्यक्तियों, गुरुओं और ज्योतिषियों की शरण में जाते रहे हैं। आस्था अपने आप में एक निजी और सम्मानजनक विषय है लेकिन जब इसी आस्था का दुरुपयोग करके अपराधों को अंजाम दिया जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का संकट बन जाता है।

हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ स्वयंभू बाबा, साधु या ज्योतिषी अपने कृत्यों को 'धार्मिक प्रक्रिया' या 'आध्यात्मिक उपचार' का नाम देकर महिलाओं के साथ शोषण, ठगी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते पाए गए हैं। इन घटनाओं ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया है।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का यौन शोषण या बलात्कार, चाहे किसी भी नाम या बहाने से किया जाए, जघन्य अपराध है। 'धार्मिक विधि', 'उपचार' या 'आध्यात्मिक क्रिया' जैसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसे कृत्यों को सही ठहराना न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानून की दृष्टि में पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह एक सुनियोजित तरीका होता है, जिसके माध्यम से अपराधी अपने प्रभाव, पद और लोगों की आस्था का लाभ उठाकर उन्हें भ्रमित करता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है-क्या केवल अपराधी ही दोषी है या पीड़ित और उसका परिवार भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं? यह सवाल समाज में अक्सर उठाया जाता है और कई बार लोग पीड़ितों पर ही उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण न केवल संवेदनहीन है बल्कि समस्या के मूल कारणों को समझने में भी बाधा बनता है।

कई मामलों में देखा गया है कि ऐसे तथाकथित धार्मिक व्यक्ति पहले लोगों का विश्वास जीतते हैं। वे खुद को चमत्कारी शक्तियों से युक्त बताते हैं, समस्याओं का त्वरित समाधान देने का दावा करते हैं और धीरे-धीरे अपने अनुयायियों पर मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे पीड़ितों को इस हद तक प्रभावित कर देते हैं कि वे सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला विरोध नहीं करती तो इसे सहमति मान लेना गंभीर भूल होगी।

इसके अलावा, सामाजिक दबाव, शर्म और बदनामी का डर भी एक बड़ा कारण होता है, जिसके चलते पीड़ित खुलकर सामने नहीं आ पाते।

हमारे समाज में आज भी यौन अपराधों को लेकर पीड़ित को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति मौजूद है। ऐसे में कई महिलाएँ चुप रहना बेहतर समझती हैं। यह चुप्पी अपराधियों के लिए एक ढाल बन जाती है और वे अपने कृत्यों को बार-बार दोहराते रहते हैं।

परिवार की भूमिका को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अगर परिवार अपने सदस्यों के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक हो तो कुछ हद तक ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति, विशेषकर वयस्क, अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार रखता है। कई बार ये मुलाकातें परिवार की जानकारी के बिना होती हैं और कई बार परिवार भी उसी अंधविश्वास का हिस्सा बन चुका होता है। इसलिए केवल परिवार को दोषी ठहराना भी एक सरलीकृत और अधूरा दृष्टिकोण होगा।

अब सवाल उठता है कि क्या देश में मौजूद सभी बाबा और ज्योतिषी ऐसे ही हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ लोगों के कृत्य पूरे वर्ग की विश्वसनीयता को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इन तथाकथित धार्मिक और ज्योतिषीय गतिविधियों से समाज को वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यवस्था में बार-बार ठगी, शोषण और अपराध के मामले सामने आते हैं तो यह संकेत है कि उस व्यवस्था में कहीं न कहीं गहरी खामी है। ऐसे में सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे इस क्षेत्र का अध्ययन करें, आंकड़े एकत्र करें और यह मूल्यांकन करें कि समाज को इससे कितना लाभ और कितना नुकसान हो रहा है।

साथ ही, कानून का सख्ती से पालन भी अत्यंत आवश्यक है।

जो लोग धर्म या आस्था का सहारा लेकर अपराध करते हैं, उनके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए होनी चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है- चाहे वह कितना ही प्रभावशाली या पूजनीय क्यों न माना जाता हो।

लेकिन केवल कानून ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज और आम जनता की है। जब तक लोग बिना सवाल किए, बिना तर्क के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक ऐसे लोग पनपते रहेंगे।

शिक्षा और जागरूकता इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान हैं। लोगों को यह समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है। आस्था व्यक्तिगत होती है, जबकि अंधविश्वास वह होता है जिसमें व्यक्ति तर्क और विवेक को छोड़ देता है।

हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और प्रश्न पूछने की आदत सिखानी होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी 'धार्मिक प्रक्रिया' के नाम पर आपसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो असामान्य, असहज या निजी सीमा का उल्लंघन करता हो तो उस पर तुरंत सवाल उठाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कानून की मदद लेनी चाहिए।

मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मीडिया को चाहिए कि वह ऐसे मामलों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करे, न कि सनसनीखेज तरीके से। साथ ही, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सकारात्मक और शिक्षाप्रद सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अंततः, यह सामूहिक जिम्मेदारी है। अपराधी को सजा दिलाना जरूरी है लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है ऐसे माहौल का निर्माण करना, जहाँ अपराध पनप ही न सके। इसके लिए कानून, समाज, परिवार और व्यक्ति- सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी।

धर्म का मूल उद्देश्य मानवता, नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देना है। यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर इन मूल्यों का उल्लंघन करता है तो वह न केवल कानून का अपराधी है बल्कि धर्म का भी अपमान करता है। ऐसे लोगों को पहचानना, उनके खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें कानून के दायरे में लाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

समय आ गया है कि हम आस्था और अंधविश्वास के बीच स्पष्ट रेखा खींचें। यह समझें कि हर वह व्यक्ति जो धार्मिक भाषा बोलता है, वह धार्मिक नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण- किसी भी परिस्थिति में अपराध को धर्म का नाम देकर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अगर समाज इस मूलभूत सत्य को समझ ले तो न केवल ऐसे अपराधों में कमी आएगी बल्कि एक अधिक जागरूक, सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना भी संभव हो सकेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव चीमा में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का किया उद्घाटन; 15 गांवों के 50 हजार निवासियों को होगा लाभ

सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को संगरूर, पटियाला और लुधियाना किया जाता था रेफर, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही इलाज उपलब्ध होगा : भगवंत मान

सिटी दर्पण संवाददाता
संगरूर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज गांव चीमा में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि 11.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित और 30 बिस्तरों वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि यह अस्पताल न केवल 15 गांवों के लगभग 50 हजार निवासियों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों की लगभग 35 से 40 हजार आबादी को भी किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराएगा।

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया, मरीजों का हालचाल पूछा और उनके परिवारों से भी बातचीत की।

अस्पतालों की बदलती तस्वीर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को अधिकतर संगरूर, पटियाला और लुधियाना रेफर किया जाता था, लेकिन अब मरीज स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक मशीनों और समर्पित इमरजेंसी तथा जच्चा-बच्चा वार्डों से सुसज्जित इस अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, संत बाबा अतर सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को तेजी से पूरा

करने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस नए अस्पताल के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने कहा, आज संत अतर सिंह जी महाराज के जन्म स्थान गांव चीमा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया है। संत अतर सिंह जी महाराज ने शिक्षा और समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया और उनके सम्मान में इस केंद्र का नाम रखा जाना गर्व की बात है। गौरतलब है कि 11.75 करोड़ रुपये की लागत वाला यह केंद्र 30 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। इस परियोजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह केंद्र 1975 में 10 बिस्तरों के साथ स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 20 बिस्तरों तक बढ़ाया गया। अब क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए इसे 30 बिस्तरों तक विस्तारित किया गया है। लगभग 50 हजार लोगों को आपातकालीन और विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाला यह केंद्र क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को यहां आपातकालीन देखभाल मिलेगी और सर्जिकल प्रक्रियाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

अस्पताल में उपलब्ध डाक्टरी सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ईएनटी और दंत सेवाओं के साथ-साथ बच्चों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध होंगे। मुफ्त जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, एक्स-रे और रक्त जांच की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए भी यहां उपचार उपलब्ध होगा।

नशे के दुष्प्रभावों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने नशों को कानूनी मान्यता देने के विचार को खारिज करते हुए कहा, यह तर्कहीन है क्योंकि एक नशा दूसरे की जगह नहीं ले सकता। इसके बजाय युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। राज्य सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पहले ही कई पहल शुरू की हैं।

राज्य में चल रही नशा विरोधी मुहिम के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान ने राज्य में नशे के कारोबार की कमर तोड़ दी है। नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं और सप्लाई चेन को तोड़ा गया है। ह्यआपह्न सरकार जल्द ही उन बहादुर लोगों को सम्मानित करेगी जिन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ अहम जानकारी दी।

प्रशासन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ह्यआपह्न सरकार ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे बड़े बदलाव आए हैं। जनता के टैक्स का पैसा जनता के हित में खर्च किया जा रहा है। विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से यह पैसा लोगों तक वापस पहुंच रहा है। सरकार ने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली, 65 हजार से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार के रोजगार, बेहतर सड़कें और बंद किए गए टोल प्लाजा से रोजाना 70 लाख रुपये की बचत सुनिश्चित की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं।ह्व

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक अमन अरोड़ा तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी उपस्थित थे।

हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े बिहार-आधारित हथियार सप्लायर सहित चार आरोपी काबू, 10 सेल्फ-लोडिंग हथियार बरामद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/पटियाला

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटियाला पुलिस ने अंतर-राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई मॉड्यूल से जुड़े चार आरोपियों को 10 आधुनिक सेल्फ-लोडिंग हथियारों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सौरभ कुमार निवासी गांव जारंग दीह, मुजफ्फरपुर (बिहार), साजन निवासी सोहाना (एसएएस नगर), अभिषेक उर्फ काका निवासी गुरदीप कॉलोनी अबलोवाल, पटियाला और इंद्रजीत सिंह उर्फ रोहित निवासी पुराना बिशन नगर, पटियाला के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी बिहार से देसी हथियार लाकर राज्य में आपराधिक गतिविधियों के लिए सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में गैंगवार के संकेत भी मिले हैं, जिसके तहत इलाके में दबदबा कायम करने के लिए गोल्डी ढिल्लों नेटवर्क से जुड़े एक विरोधी अपराधी को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी। डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस टीमों को पुख्ता सूचना मिली थी कि बिहार निवासी सौरभ कुमार अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर राज्य में टारगेट किलिंग और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधियों को देसी सेल्फ-लोडिंग पिस्तौल सप्लाई कर रहा है। एसपी इन्वेस्टिगेशन पटियाला गुरबंस सिंह बैंस और डीएसपी हरमन चीमा की निगरानी में सीआईए पटियाला यूनिट और एसएचओ शंभू ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने आगे बताया कि आरोपी सौरभ कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर की कुछ अवैध हथियार निर्माण इकाइयों से हथियारों की व्यवस्था करता था और विभिन्न माध्यमों से पंजाब में सप्लाई करता था। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अभिषेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के संपर्क में था और गैंगवार में सक्रिय रूप से शामिल था। इस संबंध में एफआईआर नंबर 50 दिनांक 01-04-2026 को पुलिस स्टेशन शंभू, पटियाला में बीएनएस की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सूद सभा लुधियाना ने प्रख्यात चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. राजीव सूद को सम्मानित किया

सिटी दर्पण संवाददाता
फरीदकोट

सूद सभा लुधियाना वेलफेयर एसोसिएशन ने सूद समुदाय के गौरवान्वित सपूत और देश के प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) राजीव सूद को उनकी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को देखते हुए दिया गया है। डॉ. राजीव सूद, जो वर्तमान में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं, का चार दशकों से अधिक का सेवा अनुभव है। उन्होंने यूरोलॉजी के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी पहचान बनाई है। कई उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने डीन और संस्थापक डीन जैसे उच्च पदों पर रहकर चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयां दी हैं। सभा के प्रतिनिधियों ने कहा कि डॉ. सूद को प्रतिष्ठित 'डॉ. साल 2017 में देश का 'बी. सी. राय नेशनल अवॉर्ड' मिला। इसके अलावा, उन्हें मिले कई नेशनल सम्मान पूरे सूद समुदाय के लिए बहुत गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉ. राजीव सूद की उपलब्धियां हमारे समाज का सिर ऊंचा करती हैं। सूद सभा लुधियाना उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और भविष्य में सफलता की दिल से कामना करती है। इस मौके पर, सभा के पदाधिकारियों ने समाज के प्रति डॉ. सूद के समर्पण की सराहना की और उम्मीद जताई कि वे इसी तरह मानवता की सेवा करते रहेंगे।

पंजाब में दलितों और मजलूमों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगाः जसवीर गढ़ी

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने पंजाब के विभिन्न जिलों में दलितों और मजलूम वर्गों से जुड़ी अत्याचार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए लगातार तीन स्व-मोटो नोटिस जारी किए हैं। चेयरमैन ने विदेश से लौटते ही इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्ण रिपोर्टें मांगी गई हैं। आयोग को प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शहीद भगत सिंह नगर के कस्बा काठगढ़ में एक महिला सरपंच और उनके पति बाबा काले शाह को बंधक बनाने, जाति आधारित गाली-गलौच करने और मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा सीनियर कप्तान पुलिस शहीद भगत सिंह नगर से 7 अप्रैल, 2026 को पूर्ण रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। दूसरे मामले में जिला होशियारपुर के गांव नूरपुर जट्टां में डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है, जिसके संबंध में आयोग द्वारा सीनियर कप्तान पुलिस होशियारपुर को 9 अप्रैल, 2026 को पूर्ण रिपोर्ट सहित पेश होने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार तीसरे मामले में जिला तरनतारन के गांव बेईपुरी में दो दलित परिवारों के साथ गांव के सरपंच द्वारा मारपीट, गाली-गलौच करने और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर वायरल हो गई हैं। इस मामले के संबंध में भी आयोग द्वारा सीनियर कप्तान पुलिस तरनतारन से 9 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट तलब की गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित डीएसपी स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पंजाब में गरीबों, मजलूमों और दलित वर्गों पर किसी भी तरह का जुल्म या जाति आधारित भेदभाव किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर आयोग द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाएगी। उन्होंने और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी किसी भी जाति भेदभाव के मामले में लापरवाही करते पाए गए तो उनके खिलाफ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन श्री गगनदीप सिंह काकू आहलूवालिया ने आज चंडीगढ़ स्थित बोर्ड के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

गगनदीप सिंह काकू आहलूवालिया ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि बोर्ड की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड द्वारा पीएमईजीपी योजना के तहत 457 इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिससे 5,027 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन इकाइयों के लाभार्थियों को कुल 32 करोड़ 77 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।इनमें से लगभग 100 इकाइयाँ 1 लाख से 10 लाख रुपये तक की लागत वाली हैं, 204 इकाइयाँ 10 लाख से 24 लाख रुपये तक की लागत वाली हैं, जबकि 153 इकाइयाँ 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की लागत वाली स्थापित की गई हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास किए जाएं और बोर्ड की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन योजनाओं का लाभ हर जिले और गांव तक पहुंच सके और अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सके।

इस अवसर पर बोर्ड के सदस्य सचिव श्री रमनदीप सिंह, सुपरिंटेंडेंट श्री दविंदर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट श्री अमित चोपड़ा, श्री अप्रीत गुप्ता, श्री जिया शाह, श्री गुरजंट सिंह पूनियां, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती अमितप्रीत कौर, मिस राधिका और श्री संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त-समाचार

स्पीकर ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वाँ सत्र 13 अप्रैल को बुलाया

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस संबंधी नियमों के नियम 16 के दूसरे उपबंध के तहत पंजाब विधानसभा स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विधानसभा की बैठक, जिसे 16 मार्च, 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, 13 अप्रैल, 2026 दिन सोमवार को सुबह 11:00 बजे पंजाब विधानसभा हॉल, विधान भवन, चंडीगढ़ में बुलाई है।

चंडीगढ़ में 4 अप्रैल को निकलेगी 23वीं विशाल शोभा यात्रा, तैयारियां जोरों पर

चंडीगढ़। श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ जी के आशीर्वाद से शहर में 4 अप्रैल को 23वीं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ सर्व सांझा सेवा मंडल (पंजीकृत) चंडीगढ़ द्वारा आयोजित की जा रही है। शोभा यात्रा श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर सेक्टर 29 से प्रारंभ होकर विभिन्न सेक्टरों से गुजरते हुए सेक्टर-42 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में संपन्न होगी। मंडल के प्रधान ओम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा की तैयारियां इन दिनों जोर-शोर से चल रही हैं। शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों, श्रद्धालुओं और मंडल के सदस्यों द्वारा इस पवित्र आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर साल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं और बाबा बालक नाथ जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। शोभा यात्रा के दौरान भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में शोभा यात्रा के लिए विशेष रूप से बाबा जी के प्रसाद स्वरूप बाबा जी के रोट (मीठी रोटी) तैयार किए जाएंगे। इसके लिए स्थान के रूप में दुर्गा मंदिर सेक्टर-41ए, चंडीगढ़ निर्धारित किया गया है। मंडल द्वारा सभी सदस्यों और श्रद्धालुओं से अपील की गई है जो भी श्रद्धालु बाबा जी के रोट बनाने की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे इस सेवा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के मार्ग को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और प्रशासन के सहयोग से इसे सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर और जल सेवा की व्यवस्था भी की जाएगी। मंडल के प्रधान ओम ठाकुर ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सेवा करने और 4 अप्रैल को निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में शामिल होकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।

आईकू ने 15 एपेक्स लॉन्च करने की घोषणा की

चंडीगढ़। आईकू ने आईकू 15 एपेक्स लॉन्च करने की घोषणा की, जो फ्लैगशिप आईकू 15 का नया कलर वेरिएंट है। आईकू 15 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, एपेक्स वेरिएंट दमदार डिजाइन के साथ फ्लैगशिप अनुभव को और बेहतर बनाता है और परफॉर्मेंस व एडवांस्ड डिस्प्ले इनोवेशन में आईकू की लीडरशिप को मजबूत करता है। आईकू 15 एपेक्स अपने बोल्ड और आकर्षक डिजाइन के साथ अलग पहचान बनाता है। एपेक्स यानी सबसे ऊंचे स्तर की अवधारणा से प्रेरित यह डिजाइन ताकत, सटीकता और आत्मविश्वास को दशार्ता है। इसके बैक पैनल में इंडस्ट्री-फर्स्ट डायनामिक पार्टिकल डिजाइन और लेजर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रोशनी के साथ बदलते हुए 3डी जैसा फ्लुइड इफेक्ट देती है, जिससे फोन चलता-फिरता जीवंत महसूस होता है। आईकू 15 एपेक्स में आईकू 15 के सभी फ्लैगशिप फीचर्स बरकरार हैं। यह भारत के सबसे तेज पड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर से लैस है, जिससे बेहतरीन स्पीड, एफिशिएंसी और इमर्सिव गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। ट्रिपल एंबिएंट लाइट सेंसर डिस्प्ले की ब्राइटनेस और कलर टोन को वातावरण के अनुसार अपने-आप एडजस्ट करते हैं, जिससे हर समय नेचुरल और कंफर्टेबल व्यूइंग अनुभव मिलता है। डॉल्बी विजन सपोर्ट और टीयूवी रीनलैंड सर्टिफाइड आई प्रोटेक्शन के साथ यह स्मार्टफोन सिनेमैटिक और आंखों के लिए सुरक्षित विजुअल अनुभव देता है।

गैलेक्सी ए 57 5जी और ए 37 5जी नए ऑसम इंटेलिजेंस एआई फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च

चंडीगढ़। सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन गैलेक्सी ए 57 5जीऔर गैलेक्सी ए 37 5जी को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये डिवाइस यूजर्स को बेहतरीन एआई अनुभव, वॉइस और ट्रांसलेशन क्षमताएं और एडवांस फोटोग्राफी फीचर्स प्रदान करते हैं। ये फोन 'ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग' (फोन के भीतर ही प्रोसेसिंग) को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्पीड, सुरक्षा और एफिशिएंसी में सुधार होता है। गैलेक्सी ए 57 5जी और ए 37 5जी में एआई का सबसे नया और खास फीचर ह्यडायरेक्ट वॉइसमेलह्न है। अगर आप कॉल नहीं उठा पाते, तो यह सुविधा कॉलर को मैसेज छोड़ने का विकल्प देती है, और खास बात यह है कि वह मैसेज आपको बिल्कुल कॉलर की असली आवाज में सुनाई देता है। एआई इसे तुरंत टेक्स्ट में बदल देता है और फोन में सुरक्षित सेव कर लेता है, यानी इसके लिए आपको नेटवर्क ऑपरेटर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही, नया एन्हांस्ड ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन फीचर भारत में अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषाओं को सपोर्ट करता है। यह आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देता है और तुरंत उसका अनुवाद कर देता है, ताकि यूजर्स उसे अपनी भाषा में पढ़ सकें।

डिप्टी कमिश्नर ने वोटरों से की बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर की जा रही वेरिफिकेशन में सहयोग देने की अपील

जालंधर। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले में प्री-एस.आई.आर गतिविधियों के तहत बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर की जा रही वेरिफिकेशन में मतदाताओं से बी.एल.ओ. का सहयोग करने की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) अप्रैल माह में शुरू होने की संभावना है। इसलिए एस.आई.आर. की प्री-गतिविधियों का काम चल रहा है, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची के मतदाताओं का मिलान/मैपिंग 2003 की मतदाता सूची के साथ किया जा रहा है।

शुद्ध जीएसटी संग्रह 26,601 करोड़ रुपये तक पहुंचा, पंजाब राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़कर आगे निकला

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब के शुद्ध जीएसटी संग्रह में 12.52% की वृद्धि दर्ज: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मजबूत वित्तीय प्रबंधन और निरंतर आर्थिक सुधार को दशार्ते हुए, पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मार्च माह तक शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 12.52% की महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य ने मार्च 2026 में वर्ष-दर-वर्ष भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें शुद्ध जीएसटी संग्रह मार्च 2025 के 1,913.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,231.93 करोड़ रुपये हो गया है। यह 318.11 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि और 16.6% की बढ़ोतरी को दशार्ता है, जबकि मार्च में एसजीएसटी नकद संग्रह में 18% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 7% की राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में यह प्रदर्शन पंजाब को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में शामिल करता है।

यहां जारी एक प्रेस बयान में इन आंकड़ों का खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब ने पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगातार और व्यापक राजस्व वृद्धि दर्ज की है। मार्च तक शुद्ध जीएसटी संग्रह 2024-25 के 23,642.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 26,601.12 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 2,959.04 करोड़ रुपये की ठोस वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा, इस निरंतर वित्तीय विस्तार ने पंजाब को राष्ट्रीय औसत से आगे रखते हुए शुद्ध जीएसटी राजस्व में लगभग 6% अधिक वृद्धि दिलाई, जिससे राज्य एक मजबूत प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थापित हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तीन चरणों वाली राजस्व प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दशार्ता है– शुरूआती मजबूत वृद्धि, जीएसटी 2.0 नीति के कारण आई गिरावट और अंतिम तिमाही में तेज रिकवरी। उन्होंने बताया कि पहले छह महीनों (अप्रैल से सितंबर 2025) में पंजाब ने शुद्ध जीएसटी संग्रह में 2,478.19 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जो 23% की वृद्धि को दशार्ती है। यह राज्य स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन और अनुपालन उपायों का परिणाम है।

जीएसटी 2.0 नीति के कारण आयी चुनौतियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में गिरावट आई, जहां शुद्ध संग्रह में 193.04 करोड़ रुपये (-3%) की कमी दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से केंद्र की नीतिगत बदलावों के कारण थी। इस चरण में लगभग 400

मार्च 2026 में 16.6% की वृद्धि, शुद्ध संग्रह 2,231.93 करोड़ रुपये तक पहुंचाः हरपाल सिंह चीमा

करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व प्रभाव पड़ा।

उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के चलते जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में तेज रिकवरी हुई। इस दौरान कुल संग्रह में 564.97 करोड़ रुपये (9%) और शुद्ध संग्रह में 669.09 करोड़ रुपये (11%) की वृद्धि हुई, जिससे पहले आई गिरावट की भरपाई हो गई और विकास की गति फिर से स्थापित हुई।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि, विशेषकर अंतिम तिमाही की मजबूत रिकवरी, राज्य सरकार की प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और कर प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ती है। राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार कर अनुपालन ढांचे को मजबूत करने, तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और ईमानदार करदाताओं को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों ने मार्च 2026 और वार्षिक आंकड़ों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो जीएसटी संग्रह में व्यापक दबाव को दशार्ता है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीएसटी संग्रह में और वृद्धि का विश्वास जताते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह राज्य सरकार के लगातार प्रवर्तन प्रयासों, बेहतर अनुपालन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण संभव होगा, जो राजस्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

32 दिनों के युद्ध के बाद ट्रंप का राष्ट्र को संदेश: ईरान की तबाही को बताया शांति का नया रास्ता

20 मिनट के संबोधन में पिछली सरकारों पर बरसे ट्रंप; बोले- ईरान अब खतरा नहीं, हमारी सेना ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है

- डोनाल्ड ट्रंप का देशवासियों से सब्र रखने का आह्वान

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

फोटोः हि.स.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हमले को ईरान और उसके सहयोगियों की लगभग आधी सदी से की जा रही हिंसा का बदला बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने बुधवार रात अमेरिकी मतदाताओं से युद्ध के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 20 मिनट के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिकी सैन्य अभियान की तारीफ की।

उन्होंने देशवासियों से सब्र रखने की अपील की। इस युद्ध को अमेरिकियों के सुरक्षित भविष्य के लिए किया गया एक निवेश बताया। राष्ट्रपति ट्रंप का यह 28 फरवरी से छिड़े युद्ध के दौरान ईरान को केंद्र में रखकर दिया गया पहला राष्ट्र के नाम संबोधन है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम मुख्य रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब हैं। उन्होंने अपना वह वादा दोहराया कि अगले दो से तीन हफ्तों में वह ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण युग में वापस भेज देंगे। उन्होंने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला करके युद्ध को और बढ़ाने की अपनी धमकी को ही दोहराया। उन्होंने कहा, ईरान का नया नेता कम कट्टरपंथी है और कहीं ज्यादा समझदार है। अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो हमारी नजरें कुछ अहम ठिकानों पर रहेंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थों के साथ काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस से संबोधन के दौरान उन्होंने अपने इस दावे को दोहराया कि अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन हासिल कर लिया है। उनके सभी मूल नेताओं की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने कहा, अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम उनके बिजली संयंत्रों पर एक साथ हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया है, जबकि इनको निशाना बनाना सबसे आसान था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की भागीदारी की तुलना आधुनिक इतिहास के दूसरे संघर्षों से की। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि हम इस संघर्ष को सही नजरिए से देखें। उन्होंने हाल के युद्धों में अमेरिका की भागीदारी की अवधि गिनाई- पहला विश्व युद्धः 1 साल, 7 महीने, 5 दिन, दूसरा विश्व युद्धः 3 साल, 8 महीने, 25 दिन, कोरियाई युद्धः 3 साल, 1 महीना, 2 दिन, वियतनाम युद्धः 19 साल, 5 महीने, 29 दिन और इराक युद्धः 8 साल, 8 महीने, 28 दिन।

उन्होंने उन लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश की जो विदेशों में कभी न खत्म होने वाले युद्धों और देश में बढ़ती गैस की कीमतों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हम सबसे ताकतवर देशों में से एक ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान में 32 दिनों से शामिल हैं। यह अभियान इतना ताकतवर और शानदार है कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और अब वह असल में हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। यह आपके बच्चों और आपके पोते-पोतियों के भविष्य के लिए किया गया एक सच्चा निवेश है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म होने के करीब है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें अभी दो से तीन हफ्ते और लगेंगे। ट्रंप ने कहा, आज रात, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ये मुख्य रणनीतिक उद्देश्य पूरे होने के करीब हैं। ट्रंप ने कहा, हमने यह सब कर दिखाया है। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है। उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है। उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। कुल मिलाकर, ये कदम ईरान की सेना को पंगु बना देंगे, आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की उनकी क्षमता को कुचल देंगे और उन्हें परमाणु बम बनाने की क्षमता से वंचित कर देंगे। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने असाधारण काम किया है।

उन्होंने युद्ध को अमेरिका की सुरक्षा और स्वतंत्र दुनिया की हिफाजत के लिए जरूरी करार दिया। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरूआत में अपने पूर्ववर्तियों की आलोचना भी की। उन्होंने दावा किया कि उनसे पहले आए अमेरिकी राष्ट्रपतियों को उनके पद संभालने से पहले ही ईरानी शासन से निपट लेना चाहिए था। ट्रंप ने कहा, हमें ईरान में रहने की जरूरत नहीं है। हमें उनके तेल की जरूरत नहीं है। हमें उनकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हम वहां अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने अमेरिका में गैस की बढ़ती कीमतों के लिए ईरानी शासन को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा, लोग गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी देखकर चिंतित हैं। यह अल्पकालिक बढ़ोतरी पूरी तरह से ईरानी शासन की कमर्शियल तेल टैंकरों और पड़ोसी देशों के खिलाफ किए गए पागलपन भरे आतंकी हमलों का नतीजा है। यह इस बात का एक और सबूत है कि परमाणु हथियारों के मामले में ईरान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता।

ट्रंप के संबोधन से पहले यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला

अबू धाबी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से कुछ देर पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर हमला किया। ईरान ने यूएई में मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। इसकी पुष्टि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने की है। सीएनएन की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार तड़के बताया कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम इस समय आने वाले मिसाइलों और ड्रोन के खतरों को रोकने का काम कर रहे हैं। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण शुरू करने से कुछ ही देर पहले दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में सायरन बज रहे हैं और जनता को सलाह दी गई है कि वे शांत रहें। साथ सुरक्षा और बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करें। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी से ईरान ने इजराइल-अमेरिका के संयुक्त हमलों के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। 31 मार्च तक यूएई रक्षा बलों ने 433 बैलिस्टिक मिसाइलों और 1,977 से अधिक ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया। कुछ हमले फुजैराह तेल क्षेत्र और दुबई हवाई अड्डे के पास हुए। इन हमलों में तीन सैन्यकर्मियों सहित 12 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने क्षेत्रीय तनाव के बीच यूएई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। यह हमला 2022 के हूती विद्रोहियों के हमले से अधिक गंभीर है।

उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस तेज भाजपा विधायक की मांग पर धामी सरकार करेगी मंथन

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

फोटोः हि.स.

उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नई बहस शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराणीसैंण में बजट सत्र के दौरान रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोरा की ओर से राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग उठाए जाने के बाद यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। सत्र के दौरान उठे इस प्रस्ताव को भाजपा के कुछ अन्य विधायकों का समर्थन मिला है, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर तत्काल निर्णय के बजाय व्यापक वैचारिक मंथन की आवश्यकता जताई है। विधायक शिव अरोरा ने सदन में राज्य की बदलती जनसंख्या संरचना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनसांख्यिकीय असंतुलन भविष्य में गंभीर चुनौती बन सकता है। उन्होंने तीन से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का सुझाव भी दिया। उनके अनुसार, इससे राज्य के संसाधनों और बजट पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मुद्दे पर भाजपा के अन्य विधायकों ने भी समर्थन जताया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित बताया।

विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने कहा कि भाजपा इस तरह के मुद्दों के जरिए एक वर्ग विशेष को निशाना बनाती है। उन्होंने टिप्पणी की कि इस प्रकार के बयान संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव एक विशेष वर्ग को लक्षित करते हैं और इसे संकीर्ण सोच करार दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून एक व्यापक नीति विषय है, जिस पर राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा आवश्यक है। रणनीतिक मामलों के जानकारों के अनुसार, यदि राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे विधायी और नीतिगत स्तर पर विस्तृत तैयारी करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि उत्तराखंड सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम उठाती है, तो उसे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि पूर्व में समान नागरिक संहिता जैसे मामलों में देखा गया है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लागू की दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली, मंत्रालयों में बढ़ा काम का दबाव

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सिंहदरबार में लंबे समय से जमी सुस्ती और नौकरशाही की जड़ता को तोड़ने के लिए नई रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की है। प्रधानमंत्री शाह ने मंत्रियों और उच्च पदस्थ कर्मचारियों को एक ही मानक में रखते हुए निर्देश दिया है कि वे हर दिन के कार्यों का विवरण शाम तक प्रस्तुत करें।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सोमवार को सभी मंत्रालयों, विभागों और आयोगों को पत्र भेजकर दिनभर किए गए सभी कार्यों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य सरकारी निकायों को इस संबंध में पत्र प्राप्त भेजा गया है। दिनभर के कार्यों का विवरण प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजने के लिए लगभग सभी मंत्रालयों ने फोकल पर्सन नियुक्त कर दिए हैं। मुख्य सचिव अर्याल के अनुसार, यह जिम्मेदारी सहसचिव स्तर के अधिकारियों को दी गई है। सरकार पहले ही सुशासन सुधार से संबंधित 100 बिंदुओं की कार्यसूची सार्वजनिक कर चुकी है। प्रधानमंत्री शाह अब इन बिंदुओं के क्रियान्वयन की दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कार्य मूल्यांकन का आधार भी इसी को बनाया है। पोखरेल ने कहा, प्रधानमंत्री सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 बिंदुओं की सरकारी कार्यसूची के आधार पर सभी मंत्रालयों को अपने काम की प्रगति रिपोर्ट हर शाम मंत्रिपरिषद कार्यालय में देनी होगी, और इसका कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

फोकल पर्सन बनाए गए सहसचिव अब हर दिन कार्यालय समय समाप्त होने से पहले कार्य विवरण तैयार करने लगे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक दिन किए गए कार्यों की रिपोर्ट शाम तक प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा टास्क निर्धारित कर पत्र जारी करने के बाद मंत्री भी अपने कार्य प्रदर्शन को लेकर सक्रिय हो गए हैं। कुछ मंत्री तो कार्यालय समय से पहले ही सिंहदरबार पहुंचने लगे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों को किया ड्यूटी फ्री

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच पेट्रोकेमिकल उत्पादों का मुख्य रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 40 प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादन से अगले तीन महीने तक के लिए पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य कच्चे माल की कीमत में होने वाली बेतहाशा वृद्धि से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुरक्षित रखना है। अमेरिका-इजराइल तथा ईरान के बीच जारी जंग के दौरान केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से फार्मास्यूटिकल, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, पैकेजिंग और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे उद्योगों को काफी फायदा होगा। कस्टम ड्यूटी हटाने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत में गिरावट आएगी और आम आदमी को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक राहत मिल सकेगा। इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में एसिटिक एसिड, एपॉक्सी रेजिन, प्यूरीफाइड टैरेफ्थैलिक एसिड, मेथेनॉल, फिनोल, टॉल्यून, एनहाइड्रस अमोनिया, एथिलीन पॉलीमर्स और कई तरह के फॉर्मल्डिहाइड पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 30 जून तक के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इन अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के इंपोर्ट से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब पश्चिमी एशिया में जियो-पॉलिटिकल टेंशन चरम पर पहुंचा हुआ है। इस टेंशन का असर दुनिया भर में अहम पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता पर पड़ना शुरू हो गया है।

मणिपुर के थौबल जिले में ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद

इंफाल। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना के आधार पर मणिपुर के थौबल जिले में हेइरोक पुलिस थानांतर्गत हेइरोक पार्ट-क्क में एक तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला-बारूद का एक जखीरा बरामद किया। फिलहाल, इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बरामदगी बुधवार को खांगाबोक महादेव चिंग इलाके से की गई, जहां सुरक्षाकर्मियों ने दो हैंड ग्रेनेड, अलग-अलग हथियारों की पांच मैगजीन और अलग-अलग कैलिबर के 2,388 राउंड गोला-बारूद जब्त किया। यह अभियान सुरक्षा एजेंसियों के उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद इस क्षेत्र में अवैध हथियारों की आवाजाही पर रोक लगाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। बरामद की गई चीजों के स्रोत और उनके इस्तेमाल के मकसद का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप पर मालदा में दूसरे दिन भी प्रदर्शन, कई जगह सड़क जाम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप को लेकर लगातार दूसरे दिन गुरुवार सुबह से कई इलाकों में प्रदर्शन और सड़क अवरोध शुरू हो गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अंतिम मतदाता सूची के साथ-साथ पूरक सूची से भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से नाराजगी बढ़ रही थी, जो अब विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आई है। मालदा विधानसभा क्षेत्र के मंगलाबाड़ी ग्राम पंचायत के नारायणपुर इलाके में 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग (कोलकाता-सिलीगुड़ी मार्ग) पर हजारों लोगों ने अवरोध किया। इसके कारण लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंग्लिश बाजार और मानिकचक क्षेत्रों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की खबर है। इस बीच मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कालियाचक-2 प्रखंड विकास कार्यालय में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े सात न्यायिक अधिकारियों का घेराव कर लिया गया था, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं। देर रात केंद्रीय बलों ने पहुंचकर सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।

जलपाईगुड़ी में ट्रेन से 14 बांग्लादेशी गिरफ्तार

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) को बड़ी सफलता मिली है। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में बीती रात अभियान चलाकर 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, सामान्य डिब्बे में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 14 संदिग्धों की पहचान कर उन्हें ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए। इसके अलावा मलेशिया की मुद्रा और मोबाइल फोन भी मिले है। जब आधार कार्ड के नंबरों की जांच की गई तो वे फर्जी पाए गए। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि सभी आरोपित बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों के रहने वाले है। वे अवैध रूप से सीमा पार कर उत्तर-पूर्व भारत में दाखिल हुए थे और कामाख्या से दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सवार हुए थे। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पहुंचने के बाद उनका जम्मू-कश्मीर जाने का भी प्लान था। आरपीएफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूची पर बवाल

- आठ घंटे बाद देररात मुक्त कराए जा सके सात अधिकारी

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक-2 प्रखंड विकास कार्यालय में विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को बुधवार देररात लगभग आठ घंटे के घेराव के बाद पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कालियाचक, मोथाबाड़ी और सुजापुर क्षेत्रों में उस समय प्रदर्शन शुरू हो गया जब अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर लोग सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के कुछ हिस्सों को भी अवरुद्ध कर दिया और मतदान से पहले सूची में सुधार की मांग की।

अधिकारियों के अनुसार, तीन महिला अधिकारियों सहित सात न्यायिक अधिकारी एसआईआर कार्य के सिलसिले में प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान दोपहर से प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव शुरू कर दिया। बाद में आधी रात बाद पुलिस सुरक्षा में उन्हें वहां से निकाला गया। बचाव अभियान के दौरान पुलिस काफिले पर हमले की कोशिश की भी खबर है। घटनास्थल से सामने आए दृश्य में एक वाहन के अंदर टूटे कांच भी दिखाई दिए हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुकांत मजूमदार ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं के कथित उकसाने वाले बयानों के कारण यह स्थिति बनी है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि उनकी पार्टी कानून को हाथ में लेने का समर्थन नहीं करती। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित कुछ छोटे दल अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सड़क जाम खोलने के लिए प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की गई। स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं, हालांकि कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर फिलहाल विस्तृत टिप्पणी नहीं की गई है।

मालदा हिंसा पर चुनाव आयोग सख्त पुलिस महानिदेशक से मांगी रिपोर्ट

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मालदा जिले में मतदाता सूची को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता से इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की जानकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल को भी दी गई है।

बुधवार को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में मालदा के मोथाबाड़ी, सुजापुर समेत कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई थी। सैकड़ो की संख्या में बाहर निकले अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता-सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 को जाम कर दिया और कालियाचक-2 प्रखंड कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि उस समय प्रखंड कार्यालय के अंदर एसआईआर कार्य में लगे सात न्यायिक अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। ये अधिकारी शाम चार बजे से रात 12 बजे तक अंदर फंसे रहे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों को निकालकर ले जाते समय पुलिस के वाहनों पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगा है। एक वाहन के अंदर टूटे हुए शीशे भी देखे गए। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारियों को छुड़ाने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों के काफिले की एक गाड़ी से एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है।

राहुल गांधी ने उठाए ईसीएचएस और विकलांगता पेंशन पर सवाल

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) में गंभीर कमियां होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन कमियों कि वजह से 72 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। योजना में प्रतिपूर्ति में देरी, दवाइयों की कमी, अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार और बकाया राशि का भुगतान न होने जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।

राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हाल ही में घायल पूर्व सैनिकों से मुलाकात के दौरान उन्हें इन समस्याओं के बारे में बताया गया। जब उन्होंने यह मुद्दा संसद में उठाया तो सरकार ने उनके सवालों को टालने की कोशिश की। सरकार के पास न बकाया रकम के बारे में कोई जानकारी है और न ही उसने देरी के कारणों पर कोई स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैग ने भी हाल में रिपोर्ट दी है कि योजना को पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया कि पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जरूरी बजट क्यों नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि विकलांग पूर्व सैनिकों की टैक्स छूट से जुड़े उनके सवाल को भी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। वित्त विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान के तहत यदि कोई सैनिक सेवा में बना रहता है, तो उसकी विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगाया जाएगा। यह इसे उन सैनिकों को सजा देने जैसा है जो देश की सेवा करते हैं।

ठगी सीआईबी की जांच में पासपोर्ट जब्त करने और जबरन बीमा क्लेम लिखवाने का सनसनीखेज खुलासा

नेपाल में 130 करोड़ का रेस्क्यू घोटाला, 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा

- 16 ट्रेकिंग और 4 हेलिकॉप्टर कंपनियां रडार पर

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों की खूबसूरती और पर्वतारोहण के जुनून की आड़ में चल रहे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के 'बीमा घोटाले' का सनसनीखेज पदार्फाश हुआ है। विदेशी पर्यटकों के फर्जी रेस्क्यू और बनावटी इलाज के नाम पर करीब 130 करोड़ रुपये की बीमा राशि डकारने के आरोप में काठमांडू जिला अदालत में 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो की इस कार्रवाई ने नेपाल के पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र के उस गठजोड़ को उजागर किया है, जो 'सेवा' नहीं बल्कि 'संगठित अपराध' में लिप्त था। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे किसी फिल्म की पटकथा जैसे लगते हैं। आरोपित एजेंसियां और अस्पताल मिलकर ऐसे पर्यटकों का 'फेक रेस्क्यू' करते थे जिन्हें वास्तव में किसी सहायता की जरूरत नहीं होती थी।

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि एवरेस्ट क्षेत्र से हेलिकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू किए गए एक पर्यटक को दिन भर काठमांडू में शॉपिंग के लिए भेजा गया और केवल शाम को अस्पताल में हाजिरी लगवाई गई। जब तक बीमा कंपनी भुगतान की गारंटी नहीं दे देती, तब तक अस्पताल संचालक पर्यटकों के पासपोर्ट अवैध रूप से जब्त कर लेते थे। मरीजों से जबरन हस्ताक्षर कराए जाते थे कि उन्हें रेस्क्यू के लिए मजबूर नहीं किया गया और वे अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट हैं। आरोपितों ने 2022 के बाद से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुल 285 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा किया था।

इस कंपनी ने 1,248 पर्यटकों का रेस्क्यू किया, जिनमें 171 मामले फर्जी पाए गए। इसके आधार पर कंपनी ने 149 करोड़ का दावा कर 130 करोड़ रुपये वसूल लिए। 471 रेस्क्यू में से 75 संदिग्ध मामले मिले, जिनके लिए 119 करोड़ का दावा किया गया। 601 रेस्क्यू में 71 मामले संदिग्ध पाए गए। अस्पताल से हेलिकॉप्टर तक शामिल सरकारी वकील रामहरी काफ्ले के अनुसार, इस सिंडिकेट में 16 ट्रेकिंग कंपनियां, 5 रेस्क्यू कंपनियां, 3 अस्पताल और 4 हेलिकॉप्टर कंपनियां शामिल हैं। सीआईबी ने आरोपितों पर राष्ट्रहित के विरुद्ध अपराध, आपराधिक लाभ, दस्तावेजी जालसाजी और संगठित अपराध जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। सीआईबी ने अब तक 10 मुख्य किरदारों को गिरफ्तार किया है, जबकि 22 अन्य अभी भी फरार हैं। हिरासत में लिए गए प्रमुख नामों में शामिल हैं: डॉ. गिर्वाणराज तिमिल्सिना संचालक, श्रिद्धि इंटरनेशनल अस्पताल, संदीप तिवारी संचालक, रॉयल हॉलीडेज एडवेंचर, जयराम रिमाल और विवेक पाण्डे माउंटेन रेस्क्यू सर्विस, रविन्द्र अधिकारी और विवेक राज थपलिया नेपाल चार्टर सर्विस, मुक्ति पाण्डे और सुवास केसी एवरेस्ट एक्सपीरियंस एंड एसोसिएट्स, पासांग शेर्पा पानोरमा हिमालय ट्रेकिंग और हवाई विशेषज्ञ राजेन्द्र बहादुर सिंह।

आरोपितों की सूची

मुक्ति पाण्डे - ऐवरेस्ट एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंस प्रा. लि., सुवास केसी - एवरेस्ट एक्सपीरियंस एंड असिस्टेंस प्रा. लि., विवेक पाण्डे - माउंटेन रेस्क्यू सर्विस, जयराम रिमाल - माउंटेन रेस्क्यू सर्विस, विवेक राज थपलिया - नेपाल चार्टर सर्विस प्रा. लि., रविन्द्र अधिकारी - नेपाल चार्टर सर्विस प्रा. लि., डॉ. गिर्वाण राज तिमल्सिना - श्रीद्धि इंटरनेशनल अस्पताल, डॉ. मिनालमा पाण्डे - स्वाकन इंटरनेशनल अस्पताल, श्याम सुन्दर कँडेल - स्वाकन इंटरनेशनल अस्पताल, संदीप ढुंगाना - हिमालयन मास्टर्स एडवेंचर्स, संदीप तिवारी - रॉयल हॉलिडे एडवेंचर, शान्त कुमार बानिया - मैजिक हिमालय ट्रेक, विनोद सापकोटा - नेपाल ट्रेक एडवेंचर, जीवन पाण्डे - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, भानु ढकाल - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, ममता भट्ट - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, चुंगला शेर्पा - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, पासांग शेर्पा - पानोरमा हिमालय ट्रेकिंग, तेनजिंग शेर्पा - पानोरमा हिमालय ट्रेकिंग, पासांग दावा शेर्पा - अल्टिच्यूट एयर, बद्री लम्साल - स्पिरिचुअल एक्सकर्शन, कवीन्द्र लम्साल - स्पिरिचुअल एक्सकर्शन, विष्णु प्रसाद लम्साल - नेपाल हाइकिंग एडवेंचर, संदीप भण्डारी - माउंटेन हेलिकॉप्टर, प्रकाश बाबु दाहाल - मनांग एयर, चन्द्र प्रसाद प्याकुरेल - अल्टिच्यूट एयर, कुमार भण्डारी - नेपाल रेस्क्यू एंड असिस्टेंस, खोमराज अधिकारी - नेपाल चार्टर सर्विस, गणेश सिलवाल - एरा इंटरनेशनल अस्पताल, श्रीराम केसी - पूर्व संचालक स्वाकन अस्पताल, राम कुमार फुयाल - वर्ल्डवाइड असिस्टेंस प्रा. लि.।

किरण पिस्दा संघर्षों को मात देकर बनीं भारतीय फुटबॉल की नई पहचान

आदिवासी पृष्ठभूमि से भारतीय टीम तकः कभी रिजेक्शन से टूटा था दिल

एजेंसी (हि.स.)
रायपुर

जब इरादे फौलादी हों और सपनों में उड़ान भरने की बेताबी हो, तो बस्तर जैसे दूरदराज के आदिवासी अंचल की पगडंडियां भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के मैदानों तक का रास्ता बन जाती हैं। छत्तीसगढ़ की 24 वर्षीय फुटबॉलर किरण पिस्दा की कहानी आज देश के लाखों युवाओं के लिए महज एक सफलता की गाथा नहीं, बल्कि 'संघर्ष से सफलता' का एक जीवंत दस्तावेज है।

हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दौरान जब अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक खिंचा, तो किरण ने वह कर दिखाया जो बहुत कम खिलाड़ी कर पाते हैं। अपनी मूल पोजीशन छोड़कर उन्होंने गोलकीपिंग की कमान संभाली और अपने अनुभव से टीम को जीत की दहलीज तक ले गईं। यह बहुमुखी प्रतिभा ही किरण को आज के दौर की सबसे खास खिलाड़ियों में से एक बनाती है। किरण पिस्दा केवल घरेलू मैदानों तक सीमित नहीं रही हैं। उन्होंने भारतीय महिला फुटबॉल का मान बढ़ाते हुए यूरोप के प्रतिष्ठित क्लब डिनामो जाग्रेब (क्रोएशिया) के लिए पेशेवर फुटबॉल खेली है। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्लब स्तर तक पहुंचना उनकी तकनीकी श्रेष्ठता और खेल के प्रति उनकी गहरी समझ को दशार्ता है। किरण का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। हालाँकि, उन्हें अपने परिवार और भाई गिरीश (जो स्वयं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं) से भरपूर समर्थन मिला, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। किरण याद करती हैं, शुरूआत में फिटनेस और मानसिक दृढ़ता की कमी के कारण राष्ट्रीय कैंप से मेरा चयन नहीं हो पाया था। वह मेरे लिए एक सबक था। मैंने हार मानने के बजाय अपनी कमियों पर काम किया।

आज अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मजबूत मानसिकता से दुनिया भर के कोचों को कर रही हैं हैरान

फोटोः हि.स.

बदलाव की कुंजीः सकारात्मक मानसिकता

किरण के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी 'मेंटल ट्रेनिंग' पर ध्यान दिया। उनके कोच योगेश कुमार जांगड़ा ने उन्हें केवल गेंद के साथ खेलना ही नहीं, बल्कि दबाव के साथ खेलना भी सिखाया। मैंने खुद को समझाया कि मैदान पर नकारात्मक सोच का सीधा असर खेल पर पड़ता है। आज मैं किसी भी पोजीशन पर खेल सकती हूँ–चाहे वह स्ट्राइकर हो, मिडफील्डर हो या फुल-बैक। एक मुकम्मल खिलाड़ी वही है जो कोच की हर रणनीति में फिट बैठे। 2022 सैफ चैंपियनशिप का हिस्सा रहीं किरण के जीवन में निराशा के पल भी आए। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एएफसी महिला एशियन कप के लिए जब उनका चयन नहीं हुआ, तो वे टूटी नहीं। किरण का कहना है कि ऊंचे स्तर पर दबाव हमेशा रहता है, लेकिन अब उन्होंने इस दबाव को अपनी ताकत बनाना सीख लिया है।

ट्राइबल गेम्सः प्रतिभा को मिला नया मंच

आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं पर बात करते हुए किरण कहती हैं कि बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच (ए७स्न्ङ्ग२४११) की जरूरत है। 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' जैसे आयोजन उसी खाई को पाट रहे हैं। उनके अनुसार, ये प्रतियोगिताएं ग्रामीण बच्चों को यह अहसास कराती हैं कि वे भी तिरंगे वाली जर्सी पहन सकते हैं। वर्तमान में किरण का पूरा ध्यान भारतीय महिला लीग (क्ष्ह्छ) में निरंतर प्रदर्शन करने पर है। उनका संदेश स्पष्ट हैः अगर चयन न हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे खिलाड़ी हैं; इसका मतलब बस यह है कि अभी मैदान पर पसीना और बहाना बाकी है। छत्तीसगढ़ की इस 'वंडर गर्ल' ने साबित कर दिया है कि अगर पैरों में दम और दिल में जज्बा हो, तो दुनिया का कोई भी गोल पोस्ट आपसे दूर नहीं है। किरण की यह कहानी भारतीय खेल जगत के बदलते स्वरूप की एक शानदार तस्वीर पेश करती है।

वीमेंस चैंपियंस लीगः आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख सेमीफाइनल में

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

फोटोः हि.स.

गत चैंपियन आर्सेनल ने वीमेंस चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में चेल्सी के खिलाफ 1-0 की हार के बावजूद कुल 3-2 के स्कोर के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पहले चरण में 3-1 की जीत के चलते आर्सेनल ने बढ़त कायम रखी और अंतिम चार में प्रवेश किया।

स्टैमफोर्ड ब्रिज में बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में चेल्सी के लिए स्जोएके नुस्केन ने स्टॉपेज टाइम (90+4) में गोल किया, लेकिन यह टीम को आगे ले जाने के लिए काफी नहीं रहा। मैच के अंतिम क्षणों में चेल्सी की वीरले बुरमान का शॉट पोस्ट से टकराया, जबकि आर्सेनल की गोलकीपर डैफ्ने वान डोम्सेलार ने नुस्केन के हेडर को शानदार तरीके से बचाया। मैच के अंत में चेल्सी की कोच सोनिया बोम्पास्तोर को रेड कार्ड भी दिखाया गया। चेल्सी ने शुरूआत से ही दबाव बनाए रखा, जिसमें सैम केर ने आक्रमण में अहम भूमिका निभाई। अब सेमीफाइनल में आर्सेनल का सामना वोल्फ्सबर्ग या लियोन में से किसी एक टीम से होगा। वहीं, दूसरे क्वार्टरफाइनल में बायर्न म्यूनिख ने शानदार वापसी करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया और कुल 5-3 के स्कोर के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मैच के 81वें मिनट में ग्लोडिस विग्गोसडॉटिर ने कॉर्नर पर हेडर से गोल कर टीम को बराबरी दिलाई, इसके बाद 84वें मिनट में लिंडा डालमैन ने गोल कर जीत सुनिश्चित की। पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से मेलविन मलार्ड ने 11वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई थी और कुल स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया था। हालांकि, दूसरे हाफ में बायर्न ने लगातार दबाव बनाया और अंततः मैच अपने नाम कर लिया। बायर्न म्यूनिख अब सेमीफाइनल में बार्सिलोना या रियल मैड्रिड में से किसी एक टीम से भिड़ेगा। अन्य क्वार्टरफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जिसमें बार्सिलोना पहले चरण में 6-2 की बढ़त के साथ रियल मैड्रिड की मेजबानी करेगा, जबकि वोल्फ्सबर्ग 1-0 की बढ़त के साथ लियोन का सामना करेगा।

सैफ अंडर-20 चैंपियनशिपः भारत ने भूटान को 5-0 से रौंदा, फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ंत

एजेंसी (हि.स.)
माले (मालदीव)

फोटोः हि.स.

गत चैंपियन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 5-0 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना 3 अप्रैल को बांग्लादेश से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल को 1-0 से हराया। भारत की इस शानदार जीत के हीरो रोहेन सिंह चाफामायुम रहे, जिन्होंने 56वें और 57वें मिनट में लगातार दो गोल दागे। इसके अलावा ओमांग डोडुम (4'), मोहम्मद अरबाश (44') और स्थानापन्न खिलाड़ी मैलेमंगाम्बा थोकचोम (90+2') ने भी गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की।

मैच की शुरूआत से ही भारतीय टीम ने आक्रामक रुख अपनाया और चौथे मिनट में ही बढ़त बना ली। बांगसन सिंह ताखेल्लाम्बाम के लंबे पास पर रोहेन ने शानदार दौड़ लगाई और बॉक्स में सटीक क्रॉस दिया, जिसे ओमांग डोडुम ने बेहतरीन अंदाज में गोल में तब्दील कर दिया। शुरूआती बढ़त के बाद भारत ने खेल पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और लगातार भूटान के गोल पर हमले करता रहा। 44वें मिनट में डोडुम के शानदार मूव पर अरबाश ने गोल कर बढ़त 2-0 कर दी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम और भी आक्रामक नजर आई। 56वें मिनट में रोहेन ने टीम के बेहतरीन संयोजन पर तीसरा गोल किया और इसके ठीक एक मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 4-0 कर दिया। मैच के अंतिम क्षणों में मैलेमंगाम्बा थोकचोम ने 90+2वें मिनट में शानदार गोल कर भारत की 5-0 की बड़ी जीत पर मुहर लगा दी।

मुझे मेरा स्वाभाविक खेल खेलने का भरोसा मिलाः रिजवी

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

फोटोः हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में जेएसडब्ल्यू और जीएमआर के स्वामित्व वाली दिल्ली कैपिटल्स ने एकाना क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरूआत की और सीजन के पहले अंक हासिल किए। 142 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम 26 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। ऐसे में समीर रिजवी (47 गेंदों में नाबाद 70 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (32 गेंदों में नाबाद 39 रन) ने पांचवें विकेट के लिए 119 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को 17.1 ओवर में जीत दिलाई। यह फ्रेंचाइजी के इतिहास में पांचवें या उससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

मैच के बाद समीर रिजवी ने कहा, जब मैं बल्लेबाजी के लिए आया तो मेरा इरादा सकारात्मक खेलने का था, लेकिन पावरप्ले में जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद स्थिति कठिन हो गई थी। मैंने और स्टब्स ने तय किया कि हमारे पास समय है, इसलिए पहले पिच को समझना जरूरी है क्योंकि गेंद स्विंग और सीम कर रही थी। उन्होंने आगे कहा, हमारी योजना सरल थी कि सेट होने के बाद ढीली गेंदों का फायदा उठाएं और परिस्थिति के अनुसार खेलें। इसी रणनीति से हमने साझेदारी बनाई। टीम मैनेजमेंट का आभार जताते हुए रिजवी ने कहा, कोच और सपोर्ट स्टाफ ने मुझे नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने और अपना स्वाभाविक खेल खेलने का पूरा भरोसा दिया है। यह स्पष्टता और आजादी मुझे आत्मविश्वास देती है। अपनी पारी के बारे में उन्होंने कहा, शुरूआत में मैंने 12-13 गेंदें खेलीं लेकिन कोई बाउंड्री नहीं आई। फिर एक ढीली गेंद मिली, जिस पर मैंने शॉट लगाया और उसके बाद मैं सहज हो गया और अपना सामान्य खेल खेल पाया। उन्होंने आगे कहा, घरेलू क्रिकेट में मैं आमतौर पर नंबर-4 पर ही बल्लेबाजी करता हूं, इसलिए इस भूमिका में मैं सहज हूं और हर मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूं। आगे की निरंतरता को लेकर रिजवी ने कहा, मैंने अभी आईपीएल में ज्यादा पारियां नहीं खेली हैं, इसलिए मेरा फोकस अब लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और टीम के लिए योगदान देने पर है।

गेंदबाजी में भी दिल्ली कैपिटल्सहै का प्रदर्शन शानदार रहा। लुंगी एनगिडी ने 3/27, टी नटराजन ने 3/29 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 2/31 और कप्तान अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 1/17 का योगदान दिया। इन प्रयासों की बदौलत लखनऊ को 141 रन पर रोक दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स अब 4 अप्रैल 2026 को अरुण जेटली स्टेडियम में अपने पहले घरेलू मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना करेगी और जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

फिडे कैंडिडेट्स 2026, राउंड 4ः सिंदारोव ने कारुआना को हराकर बनाई एकल बढ़त

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

साइप्रस में खेले जा रहे फिडे कैंडिडेट्स 2026 के राउंड 4 में उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व नंबर-3 फैबियानो कारुआना को हराकर अंक तालिका में एकल बढ़त हासिल कर ली।

सिंदारोव ने मुकाबले में 27.d5 की सटीक चाल के साथ केंद्र में जोरदार ब्रेक किया, जिससे खेल का रुख पूरी तरह उनके पक्ष में हो गया। इसके बाद Rxf5 जैसी महत्वपूर्ण चाल ने कारुआना को रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया। काले मोहरों के साथ खेल रहे कारुआना ...Kh8 के बाद पूरी तरह बचाव में नजर आए, जबकि सिंदारोव ने Qg4+, Bd4+ और Rc5 जैसी सटीक चालों के दम पर लगातार दूसरा जीत दर्ज की। अन्य मुकाबलों में जर्मनी के मथियास ब्लूबाउम और भारत के आर प्रज्ञानानंद के बीच कड़ा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। महिला वर्ग में भारत की आर वैशाली ने भी ड्रॉ खेला। उनके मुकाबले में स्थिति पूरी तरह जटिल हो गई थी, जहां किसी भी तरह का प्यादा ब्रेक या किंग को सक्रिय करना जोखिम भरा साबित हो सकता था। अंततः तीन बार समान स्थिति बनने पर मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। वैशाली अब तक में अजेय बनी हुई हैं। वहीं, भारत की दिव्या देशमुख को इस राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन की झू जिनेर ने पराजित किया। दिव्या ने 21वीं चाल के आसपास अपनी क्वीन को केंद्र में लाकर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन समय के दबाव में a4 चलना महंगा साबित हुआ, जबकि Re6 बेहतर विकल्प था।

दर्पण विशेष

गुड फ्राइडेः मानवता के लिए महाबलिदान और प्रेम की सर्वोच्च गाथा

गुड फ्राइडे केवल ईसाई समुदाय का पर्व नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए त्याग, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम का एक सार्वभौमिक संदेश है। यह वह दिन है जब ईसा मसीह (जीसस क्राइस्ट) ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग कर दुनिया को प्रेम का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। 'गुड फ्राइडे' का दिन हमें एक ऐसी शांति और गंभीरता की ओर ले जाता है जो सीधे आत्मा को झकझोरती है। कैलेंडर के पन्नों पर यह केवल एक छुट्टी या सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह उस निस्वार्थ प्रेम, असीम धैर्य और करुणा की पराकाष्ठा का स्मरण है, जिसने दो हजार साल पहले जेरूसलम की पहाड़ियों पर मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था।

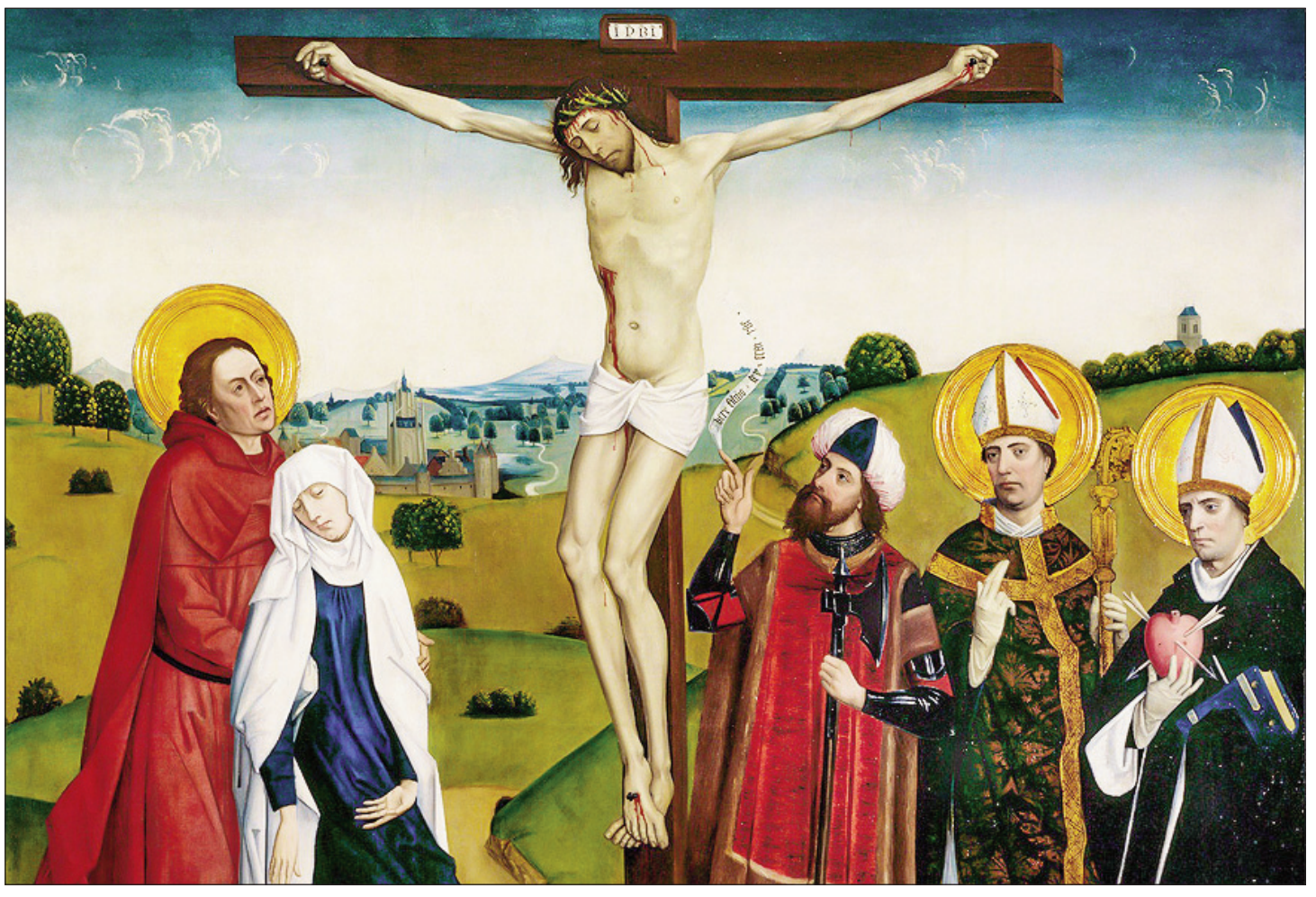

महत्व

गुड फ्राइडे का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। यह वह दिन है जब ईसा मसीह को जेरूसलम में रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातस के आदेश पर सूली पर चढ़ाया गया था। गिरफ्तारी और मुकदमाः ईसा मसीह को उनके ही एक शिष्य, जुदास इस्केरियोट के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार किया गया था। उन पर राजद्रोह और धर्म के अपमान का झूठा आरोप लगाया गया था क्योंकि वे उस समय के धार्मिक कट्टरपंथियों और रोमन साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यातना का सफरः सूली पर चढ़ाने से पहले ईसा को कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए और उन्हें अपना भारी क्रॉस खुद उठाकर 'कलवारी' नामक पहाड़ी तक ले जाना पड़ा। महान बलिदानः दोपहर के समय उन्हें सूली पर कीलों से ठोंक दिया गया। बाइबल के अनुसार, उस समय दोपहर में भी पूरी धरती पर अंधेरा छा गया था और ईसा ने मानवता के लिए अपने प्राण त्याग दिए।

उद्देश्य

इस दिन को मनाने के पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक उद्देश्य छिपे हैंः पापों का प्रायश्चितः ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार, ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उनका उद्देश्य स्वयं का बलिदान देकर मनुष्यों को उनके अपराधबोध और पापों के दंड से मुक्त करना था। क्षमा का संदेशः सूली पर लटके होने के बावजूद ईसा ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की– हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया को 'क्षमा' की शक्ति सिखाना है। सत्य और अहिंसा की जीतः यह दिन याद दिलाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।

परंपराएं और विधि

यह दिन किसी उत्सव या त्यौहार की तरह नहीं, बल्कि एक शोक और उपवास के दिन के रूप में मनाया जाता हैः मौन और प्रार्थनाः चर्चों में घंटियाँ नहीं बजाई जातीं। लोग काले या गहरे रंग के कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं और ईसा के अंतिम सात शब्दों पर ध्यान करते हैं। उपवास : बहुत से लोग इस दिन केवल एक समय सादा भोजन करते हैं या पूर्ण उपवास रखते हैं ताकि वे ईसा के कष्टों को महसूस कर सकें। चर्च की सादगीः चर्च की वेदियों से सजावट हटा दी जाती है और क्रॉस को ढंक दिया जाता है। दोपहर 3 बजे (जिस समय ईसा ने प्राण त्यागे थे) विशेष प्रार्थना सभाएं होती हैं। पवित्र शनिवार और ईस्टरः गुड फ्राइडे के बाद आने वाला शनिवार शांति का होता है, और रविवार को 'ईस्टर' मनाया जाता है, जो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी का दिन है।

इस वर्ष की प्रासंगिकता

आज 2026 में, जब दुनिया युद्धों, जलवायु परिवर्तन और आपसी वैमनस्य के दौर से गुजर रही है, गुड फ्राइडे का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैसे नफरत की दीवारें ऊंची हो रही हैं। ऐसे में ईसा मसीह का वह बलिदान हमें याद दिलाता है कि 'बदला' लेने से कहीं ज्यादा शक्ति 'बलिदान' और 'क्षमा' में है। अस्पतालों में सेवा दे रहे नर्सें हों, सीमा पर डटे सैनिक हों या वे लोग जो दूसरों की मदद के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं–उन सभी में हमें गुड फ्राइडे की वह भावना दिखाई देती है। सच्चा 'गुड फ्राइडे' वही है जब हम अपने भीतर के 'अहंकार' और 'द्वेष' को सूली पर चढ़ा दें और प्रेम के नए मार्ग पर चलें।

अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा

गुड फ्राइडे हमें सिखाता है कि दुःख स्थाई नहीं है। यह दिन केवल 'मौत' का शोक नहीं है, बल्कि 'ईस्टर' यानी पुनरुत्थान की उस आशा की पूर्वसंध्या है, जो तीन दिन बाद आने वाली है। अगर आज अंधकार है, तो रविवार को प्रकाश भी आएगा। अगर आज हार हुई है, तो जीत सुनिश्चित है। गुड फ्राइडे हमें इसी 'धैर्य' का पाठ पढ़ाता है।

शोक के दिन को 'गुड' क्यों कहा गया

एक सहज प्रश्न जो अक्सर नई पीढ़ी या अन्य समुदायों के मन में कौंधता है, वह यह है कि जिस दिन ईसा मसीह को इतनी अमानवीय यातनाएं दी गईं, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उस दिन को 'गुड' यानी 'अच्छा' क्यों कहा जाता है? इतिहास और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे 'गुड' शब्द का पुराना अर्थ 'पवित्र' छिपा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह दिन इसलिए 'भला' है क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार, इसी दिन प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया के पापों और बुराइयों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर स्वयं को बलिदान कर दिया। यह दिन इंसानियत की मुक्ति के मार्ग का द्वार खुलने का प्रतीक है। अनुभवी पत्रकारों की भाषा में कहें तो, यह न्याय पर अन्याय की अस्थायी जीत लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु पर जीवन और घृणा पर प्रेम की अंतिम विजय की आधारशिला थी।

इतिहास के वे काले घंटे

बाइबल के वृत्तांतों के अनुसार, उस शुक्रवार की दोपहर कुछ अलग थी। ईसा मसीह को जब 'कलवारी' नामक स्थान पर ले जाया गया, तो उनके सिर पर कांटों का ताज था और उनके शरीर पर कोड़ों के अनगिनत निशान। जिस शख्स ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खाना खिलाया और शांति का संदेश दिया, उसे ही 'राजद्रोह' और 'ईशनिंदा' के झूठे आरोपों में सूली की सजा दी गई। दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक, जब वे सूली पर लटके थे, कहते हैं कि आसमान में अंधेरा छा गया था। धरती डोल उठी थी। वह तीन घंटे का समय ईश्वर और मनुष्य के बीच के उस अटूट प्रेम का गवाह बना, जहाँ दर्द की पराकाष्ठा के बीच भी ईसा के होंठों पर अपने शत्रुओं के लिए केवल प्रार्थना थी– हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो यह वाक्य दुनिया के इतिहास में क्षमा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण है।

विविधता में आस्था का संगम

भारत, जो अपनी विविध संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, यहाँ गुड फ्राइडे का नजारा बेहद मार्मिक और गरिमामय होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चर्चों में आज के दिन कोई घंटी नहीं बजती। संगीत खामोश रहता है और उत्सव के रंग गायब रहते हैं। केरल के चर्च और 'पेसाहा' की परंपराः दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में, गुड फ्राइडे की गहराई देखते ही बनती है। यहाँ 'वे ऑफ द क्रॉस' की झांकियां निकाली जाती हैं, जहाँ श्रद्धालु भारी लकड़ी के क्रॉस को कंधे पर उठाकर मीलों चलते हैं। सीरियन क्रिश्चियन समुदायों में 'पेसाहा अप्पम' और कड़वे पेय का सेवन किया जाता है, जो संघर्ष और दुःख का प्रतीक है। गोवा का पुर्तगाली प्रभावः गोवा के पुराने चर्चों में आज भी मध्यकालीन सादगी और गंभीरता दिखाई देती है। यहाँ के 'पैशन प्ले' (मसीह के अंतिम घंटों का मंचन) को देखने के लिए केवल ईसाई ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग जुटते हैं। उत्तर-पूर्व की मौन प्रार्थनाएंः मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में, जहाँ ईसाई धर्म बहुसंख्यक है, पूरा समाज आज के दिन उपवास रखता है। वहाँ की पहाड़ियों में गूंजते करुण गीत वातावरण को एक अजीब सी रूहानियत से भर देते हैं।

मौन ही जिसकी भाषा है

गुड फ्राइडे के दिन चर्चों में होने वाली विशेष प्रार्थनाओं में 'सात अंतिम शब्दों' पर चिंतन किया जाता है। शाम के समय 'क्रॉस का चुंबन' की रस्म होती है, जहाँ भक्त लकड़ी के क्रॉस के सामने नतमस्तक होकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस दिन न तो मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और न ही वेदी पर कोई कपड़ा बिछाया जाता है। यह पूर्णतः 'शून्य' होने का दिन है।

आयुक्त विनय कुमार के नेतृत्व में नगर निगम पंचकूला द्वारा सभी सेक्टरों में सुबह का निरीक्षण अभियान तेज

15वें से 17वें दिन तक के निरीक्षणों से पंचकूला में साफ-सफाई और नागरिक प्रबंधन को मिला बढ़ावा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नगर निगम पंचकूला के आयुक्त श्री विनय कुमार के नेतृत्व में चल रहा प्रातःकालीन निरीक्षण अभियान पूरे शहर में साफ-सफाई, नागरिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। अभियान के 15वें दिन सेक्टर-10 में निरीक्षण किया गया, जिसमें घर-घर कूड़ा संग्रहण, स्वच्छता व्यवस्था, सड़कों एवं नालियों की मरम्मत, बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा पार्कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया गया। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (फ्हअ) ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं, जिनके समाधान हेतु मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

आसमान फाउंडेशन और मेशान फाउंडेशन के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें नाटक और नृत्य के माध्यम से साफ-सफाई और कूड़े को अलग-अलग करने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा, ट्रिनिटी क्लीनलेनेस (एनजीओ) ने नगर निगम के साथ मिलकर, कूड़ा जमा होने वाली जगहों को सुंदर जगहों में बदलने में अपना सहयोग दिया। अभियान के 16वें दिन, सेक्टर-15 में हुए निरीक्षण में घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की सफाई, बाजार क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण और वेंडिंग जोन के नियमन की समीक्षा की गई।

आयुक्त ने कूड़ा जमा होने वाली जगहों की रोजाना सफाई के निर्देश दिए और बिजली-पानी की अनियमित आपूर्ति के मामलों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे को तुरंत यूएचबीवीएन (वल्ह्श्ठ) के साथ उठाएँ और पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करें। मेशान और आशमान फाउंडेशन के बच्चों ने साफ-सफाई और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। 17वें दिन, सेक्टर-19 का निरीक्षण किया गया, जिसमें वेंडिंग जोन की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, यातायात प्रबंधन, कूड़ा जमा होने वाली जगहों और पार्कों के रखरखाव की समीक्षा की गई।

अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी चिंताएँ व्यक्त की, जिनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ह्यआसमान फाउंडेशन' के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और छात्रों को स्वच्छता तथा सामुदायिक भागीदारी के महत्व के प्रति जागरूक किया। आयुक्त श्री विनय कुमार ने दोहराया कि इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य निरंतर निगरानी, समस्याओं का त्वरित समाधान और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे पूरे पंचकूला में स्वच्छता और नागरिक प्रबंधन में स्पष्ट सुधार देखने को मिलें। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम एक स्वच्छ, हरा-भरा और नागरिक-केंद्रित पंचकूला बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पीजीआई में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पीजीआई के पीडियाट्रिक्स विभाग ने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 के अवसर पर एक सार्थक और समावेशी कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑटिज्म थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में ऑटिज्म को केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक अनुभवों के संदर्भ में समझने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीजीआई के डीन डॉ.संजय जैन मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों में ऑटिज्म की प्रारंभिक पहचान, समावेशी शिक्षा और परिवारों के लिए मजबूत सहायता तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर बाल न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र हुए। सभी ने मिलकर ऑटिज्म से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बहु-विषयक सहयोग की जरूरत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में आभा शर्मा जोशी, कर्नल (डॉ.) देव, प्रो. अंबुज, कविता दास, नेहा और गीता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा रोटरैक्ट क्लब, एम्स मोहाली के सदस्य, नर्सिंग स्टाफ, मनोविज्ञान के छात्र, अभिभावक और समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वाइस ऑफ ऑटिज्म सत्र रहा, जिसमें अभिभावकों और देखभाल करने वालों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की देखभाल में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे लगातार थेरेपी, शिक्षा में विशेष व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और सामाजिक कलंक जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं, जिनसे परिवारों को जूझना पड़ता है।

कार्यक्रम के दौरान एक ऑटिज्म से ग्रस्त युवा, जो पीजीआई में जन्मा था, ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। वह आज क्रिकेट की आवाज नाम से यूट्यूब चैनल चला रहा है और अन्य लोगों से जुड़कर अपने अनुभव साझा करना चाहता है। उसकी कहानी ने उपस्थित लोगों को प्रेरित किया और यह संदेश दिया कि ऑटिज्म के बावजूद जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में केक कटिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया, जो एकता, खुशी और विविधता के उत्सव का प्रतीक बना। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर समावेशी समाज बनाने का संकल्प लिया। रोटरैक्ट क्लब, एम्स मोहाली ने भी जागरूकता और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

नगराधीश ने जनसमस्याएं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

जिले में आमजन की समस्याओं के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे ह्यसमाधान शिविरह्व के तहत आज नगराधीश जागृति ने लघु सचिवालय के सभागार में लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को बिना विलंब समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। गांव सुंदरपुर बरवाला के एक निवासी ने शिकायत दी कि गांव में एससी समाज की चौपाल और उसके आसपास की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कब्जा हटवाने की मांग की। इस पर संज्ञान लेते हुए नगराधीश ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बरवाला को मौके का निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जा सके। वहीं, रतपुर कॉलोनी, पिंजौर के एक निवासी ने शिकायत दी कि कॉलोनी के कुछ लोग उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। इस पर नगराधीश ने पुलिस विभाग को तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीएम विंडो के एमिनेंट सिटीजन, पिंजौर को मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

नगराधीश ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिलावासियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का शीघ्र निवारण हो। उन्होंने बताया कि ह्यसमाधान शिविरह्व लोगों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की मंशा है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जाता है , जिनमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष चौहान, अरुण सिंहमार, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन परमजीत सिंह, नीरज कुमार सहित हरियाणा शहरी प्राधिकरण, नगर निगम, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी, पुलिस, शिक्षा, वन, बागवानी, कृषि एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही पर कार्रवाई, पटवारी चार्जशीट व प्रशिक्षु को नोटिस के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज जिले में गिरदावरी की पड़ताल एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे की गहन समीक्षा की। इस दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर एक पटवारी को चार्जशीट करने तथा एक प्रशिक्षु पटवारी को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने प्रातः 8 बजे से विभिन्न गांवों का दौरा किया और लगभग डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर खेतों में पहुंचकर प्रत्येक खसरे का मिलान किया। निरीक्षण के दौरान पटवारी द्वारा दर्ज प्रविष्टियों और मौके पर मौजूद फसलों में विसंगतियां पाई गईं। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने हल्का काजमपुर, तहसील रायपुररानी के पटवारी अमित को तत्काल प्रभाव से चार्जशीट करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षु पटवारी श्रीमती मीनाक्षी को डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूर्ण न करने पर शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। श्री सतपाल शर्मा ने सर्वप्रथम गांव भूड़, तहसील रायपुररानी में गिरदावरी की पड़ताल की ।इसके उपरांत उन्होंने वहां संचालित एक स्क्रीनिंग प्लांट का भी औचक निरीक्षण कर सरकार द्वारा जारी एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक बरवाला के गांव टाबर, सुल्तानपुर तथा कोट में भी गिरदावरी की गहन जांच की। इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह, तहसीलदार पंचकूला श्री सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार श्री हरदेव सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सांख्यिकीय सुदृढ़िकरण सहायता उप-योजना के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, सैक्टर-1, में सांख्यिकीय सुदृढ़िकरण सहायता उप-योजना के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय ह्यह्यआंकड़ों पर आधारित और प्रभावी शासन के लिए मानव संसाधनों को सुदृढ़ बनानाह्यह्यथा। इस प्रशिक्षण में हरियाणा के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग के 30 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों की व्यवसायिक क्षमताओं, प्रशासनिक दक्षता और कौशल विकास को बढ़ाना था, ताकि शासन में आंकड़ों और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग के निदेशक श्री मनोज कुमार गोयल के स्वागत भाषण से हुआ, जिसके बाद हरियाणा सरकार के वित्त एवं योजना विभाग के विशेष सचिव डॉ0 जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने सरकारी विभागों में नीति निर्माण, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में डेटा एनालिटिक्स के प्रभावी उपयोग और एआई का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग पर प्रकाश डाला। पहले सत्र में सॉफ्ट स्किल्स डेवल्पमैंट लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवल्पमैंट के विषय पर प्रियंका पुनिया द्वारा अपना व्याख्यान दिया गया। दूसरे सत्र में वीके धमिजा, सेवानिवृत मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सेवा मामलों पर अपना व्याख्यान दिया गया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सेवा नियमों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक प्रथाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

सजगता, तनाव प्रबंघन के लिए तकनीकें, भोजन, योगासन और भावनात्मक बुद्धिमताह्यह्य विषय पर अंतिम सत्र सुश्री प्रियंका पुनिया द्वारा संचालित किया गया। उन्होंने कार्यस्थल के तनाव को प्रबंधित करने और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सजगता, स्वस्थ जीवनशैली और भावनात्मक बुद्धिमता की भूमिका पर प्रकाश डाला, जो अंततः उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार प्रक्रिया में योगदान देता है। कार्यक्रम का समापन विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री आरके मोर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें वक्ताओं के बहुमूल्य योगदान और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी को स्वीकार किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने ज्ञान सांझा करने और क्षमता निर्माण के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान किया, जिससे अधिक प्रभावी और डेटा आधारित शासन के लिए मानव संसाधनों को मजबूत करने में योगदान मिला।

कुरुक्षेत्र विवि के छात्र-छात्राएं नेचर कैंप थापली मे प्रकृति के साथ बिताएंगे तीन दिन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विधार्थी नेचर कैंप थापली में तीन दिवसीय शैक्षणिक एवं साहसिक भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा इको-टूरिज्म के महत्व के बारे में व्याख्यान प्रदान किया जाएगा तथा दूसरे दिन ट्रैकिंग गतिविधि आयोजित की जाएगी। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेचर कैंप थापली में आयोजित ट्रैकिंग कार्यक्रम में हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं में पर्यावरण जागरूकता, साहसिक भावना तथा नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं। इस अवसर पर डिप्टी रेंज अधिकारी विद्यार्थियों को इको-टूरिज्म के विभिन्न आयामों से अवगत करेंगे तथा सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे ।उन्होंने विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के महत्व पर विशेष बल दिया जाएगा। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस तीन दिवसीय विशेष भ्रमण कार्यक्रम कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

यूआईडीएआई ने मैपल्स ऐप में अधिकृत आधार केंद्र प्रदर्शित करने के लिए मैपमाईइंडिया के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आईडीएआई) ने मैपमाईइंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत आने वाले महीनों में उनके मैपल्स ऐप पर अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित किया जा सकेगा। यह कदम निवासियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा। इस कदम से लोगों को अधिकृत आधार केंद्रों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही, निवासियों को दी जाने वाली वयस्क नामांकन, बाल नामांकन या केवल पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसी सेवाओं की प्रकृति के आधार पर आधार केंद्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस सहयोग का उद्देश्य जनसुविधा को बढ़ाना, गलत सूचनाओं से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को देशभर में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्रों (एएसके) और अन्य आधार केंद्रों तक निर्बाध पहुंच प्राप्त हो। इस समझौते पर 1 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए। यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार ने कहा, यूआईडीएआई की सेवाओं के मध्य में हमेशा निवासी रहे हैं। इस तरह के सहयोग से पूरे भारत में सत्यापित आधार केंद्रों की डिजिटल मैपिंग संभव हो सकेगी और लोगों को अधिकृत आधार केंद्र सरलता से खोजने में मदद मिलेगी। अगले कुछ महीनों में इसके लागू होने के बाद, यह सुनिश्चित होगा कि जब उपयोगकर्ता मैपल्स ऐप पर खोज करें, तो उन्हें अधिकृत आधार केंद्रों की ओर निर्देशित किया जाए। मैपमाईइंडिया, यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की गई आधार केंद्र जानकारी को मैपल्स प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेगा और आधार केंद्रों का सटीक प्रतिनिधित्व, डिजिटल मैपिंग और अलग-अलग सूची सुनिश्चित करेगा। मैपमाईइंडिया के सह-संस्थापक और सीएमडी राकेश वर्मा ने कहा, यूआईडीएआई की सेवा करना और मैपल्स ऐप के माध्यम से लोगों को आधार केंद्रों तक सुगम पहुंच प्रदान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर सिंगल थीम वर्कशॉप

चंडीगढ़। 4 और 5 अप्रैल 2026 को पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर सिंगल थीम वर्कशॉप होगी। वर्कशॉप पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की न्यूबॉर्न यूनिट द्वारा आयोजित की जाएगी। वर्कशॉप का उद्घाटन पीजीआईके डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल करेंगे। ऑर्गनाइजिंग कमिटी के चेयरपर्सन प्रो. प्रवीण कुमार हैं; ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी प्रो. सौरभ दत्ता हैं; और जॉइंट ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. जोगेंद्र कुमार हैं। अन्य फैकल्टी मेंबर्स में तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) से डॉ. नवीन जैन और नई दिल्ली से डॉ. नवीन गुप्ता; गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ से प्रो. दीपक चावला, प्रो. सूक्ष्म जैन, और डॉ. सुप्रीत खुराना शामिल हैं; और पीजीआईसे डॉ. साजन सैनी, डॉ. बिजयलक्ष्मी बेहरा, प्रो. नवीन संख्यान, डॉ. आरुषि सैनी, डॉ. अनुप्रिया कौर, डॉ. चिराग आहूजा, और डॉ. भारती शर्मा। नियोनेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऐसी बीमारियाँ शामिल हैं जो नए जन्मे बच्चों के नर्वस सिस्टम, खासकर दिमाग पर असर डालती हैं। एक समय था जब न्यूबोर्न स्पेशलिस्ट का मुख्य फोकस समय से पहले जन्मे बच्चों या एस्फिक्सिया के साथ पैदा हुए फुल-टर्म बच्चों की जान बचाना था। कुछ दशक पहले की तुलना में आज सर्वाइवल रेट में काफी सुधार के साथ, फोकस सिर्फ सर्वाइवल से हटकर न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट सर्वाइवल पक्का करने पर आ गया है। न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है बचपन और बड़े होने तक एक मेंटली और फिजिकली नॉर्मल इंसान के तौर पर जीवित रहना जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और समाज में योगदान दे सके। अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर डिसेबिलिटी के साथ बड़ा होता है और ज़िंदगी भर केयरगिवर्स पर डिपेंडेंट रहता है, तो नए जन्मे बच्चे को बचाने के लिए परिवार और समाज के बहुत सारे रिसोर्स खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। 2021 में भारत समेत कम और मध्यम आय वाले देशों के डेटा के एक सिस्टमैटिक एनालिसिस में बताया गया कि 1 ँ से कम वजन वाले बच्चों के बचने की औसत दर लगभग 30% थी, और लगभग 20% बच्चों का न्यूरोलॉजिकल विकास असामान्य था। भारत के बड़े सेंटर्स के डेटा से पता चलता है कि बहुत से लेकर मध्यम रूप से प्रीमैच्योर बच्चों में फुल-टर्म बच्चों की तुलना में ब्रेन डिसऑर्डर का खतरा लगभग पाँच गुना ज्यादा होता है, और 1 ँ से कम वजन वाले लगभग 35-40% बच्चों की या तो मौत हो जाती है या उन्हें ब्रेन में गंभीर दिक्कतें होती हैं। नए जन्मे बच्चे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए खास तौर पर कमजोर होते हैं क्योंकि उनका दिमाग नाजुक होता है। प्रीमैच्योर बच्चों में, नाजुक ब्लड वेसल के कारण ब्रेन में अंदरूनी ब्लीडिंग, खून की सप्लाई में कमी या सूजन के कारण व्हाइट मैटर को नुकसान, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में रुकावट का खतरा होता है। फुल-टर्म बच्चों में, बर्थ एस्फिक्सिया, मेटाबोलिक गड़बड़ी, या गंभीर पीलिया के कारण ब्रेन इंजरी हो सकती है।

हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल एसजीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की: विनय प्रताप सिंह

पंचकूला। हरियाणा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य जीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) राजस्व की वृद्धि दर के आधार पर देश के सभी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है । पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसजीएसटी राजस्व में राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने हरियाणा को भारत के सभी राज्यों में एसजीएसटी राजस्व वृद्धि में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया है। हरियाणा का सकल एसजीएसटी संग्रह (पोस्ट-सेटलमेंट) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,289 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संग्रह से 8,546 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, सकल एसजीएसटी (पोस्ट-सेटलमेंट) संग्रह के मामले में, हरियाणा वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश में 6वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9वें स्थान पर था। 1 अप्रैल 2026 को हरियाणा में 6,30,818 पंजीकृत करदाता हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करदाता आधार में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जीएसटी के लागू होने के बाद के वर्षों में करदाताओं की संख्या में स्थिर वृद्धि दिखाई दी है। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी दरों में सुधारों के बाद, हरियाणा राज्य एसजीएसटी संग्रह में प्रशंसनीय वृद्धि दिखा रहा है, जो राज्य की उभरती अर्थव्यवस्था और डेटा विश्लेषण संचालित कर प्रशासन को दशार्ता है।

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 | **और सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई अभियान ने दूसरे दिन को व्यस्त और सार्थक बनाया**

पीजीआईके निदेशक ने पौधरोपण अभियान और हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व किया; हाथ की स्वच्छता पर क्विज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का दूसरा दिन, जीवंत और व्यापक गतिविधियों से भरा रहा, जिसने एक स्वच्छ, हरा-भरा और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया। आज चार अलग-अलग गतिविधियाँ आयोजित की गईं – एक वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता पर एक हस्ताक्षर अभियान, जिसका नेतृत्व स्वयं पीजीआईके निदेशक प्रो. विवेक लाल ने किया। इसके अलावा, सफाई के काम में सबसे आगे रहने वाले कर्मचारियों के लिए हाथ की स्वच्छता पर एक क्विज और पीजीआईपरिसर के आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्रों में एक व्यापक सफाई अभियान भी चलाया गया।

दूसरे दिन की सबसे खास बात पीजीआईपरिसर में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान था, जिसका नेतृत्व पीजीआईके निदेशक प्रो. विवेक लाल ने सबसे आगे रहकर किया। इस गतिविधि में उप निदेशक श्री पंकज राय, चिकित्सा अधीक्षक प्रो. विपिन कौशल, फैकल्टी सदस्य, सफाई कर्मचारी और अस्पताल के कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया ।इस अभियान ने न केवल सफाई के प्रति, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति भी संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया – यह मानते हुए कि हरे-भरे स्थान और वृक्षारोपण, उपचार और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले वातावरण का एक अभिन्न अंग हैं। संस्थान के वरिष्ठ नेतृत्व को सफाई के काम में सबसे आगे रहने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से पौधे लगाते देखना, 'स्वच्छ भारत' की भावना का एक सशक्त प्रतीक था।

दिन की स्वच्छता गतिविधियों के हिस्से के रूप में एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों, फैकल्टी, रेज़िडेंट्स और अन्य प्रतिभागियों को अभियान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके, सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की औपचारिक शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह अभियान सामूहिक स्वामित्व का एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य साबित हुआ – जो केवल जुबानी शपथ तक सीमित न रहकर, एक स्वच्छ और स्वास्थ्यकर संस्थान को बनाए रखने में हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी की लिखित और व्यक्तिगत पुष्टि बन गया। इस अभियान में संस्थान समुदाय के सभी वर्गों से व्यापक भागीदारी देखने को मिली।

स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन की नियोजित गतिविधियों के हिस्से के रूप में, सैनिटरी अटेंडेंटऔर हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एक हैंड हाइजीन क्विज आयोजित किया गया। इस क्विज को हाथ धोने की सही तकनीकों, देखभाल के माहौल में महत्वपूर्ण संपर्क बिंदुओं और संक्रमण की रोकथाम के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में ज्ञान की जाँच करने और उसे मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों को नियंत्रित करने में हैंड हाइजीन सबसे अधिक लागत-प्रभावी और साक्ष्य-आधारित उपायों में से एक बना हुआ है; और स्वच्छता तथा हॉस्पिटल अटेंडेंट के रूप में काम करने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को इस ज्ञान से लैस करना पीजीआईके गुणवत्ता और सुरक्षा एजेंडा का मुख्य केंद्र है। प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया, और सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं के प्रति अपनी जागरूकता तथा प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। संस्थान की सीमाओं से बाहर भी स्वच्छता गतिविधियों का विस्तार करने के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए, पीजीआईने अपने परिसर के आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों में एक स्वच्छता अभियान आयोजित किया। स्वच्छता कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने संस्थान के निकट स्थित सार्वजनिक स्थानों, पैदल चलने के रास्तों और सामुदायिक क्षेत्रों की सफाई की; यह कार्य पीजीआईकी नागरिक जिम्मेदारी की भावना और एक सामुदायिक स्वास्थ्य अग्रणी के रूप में उसकी भूमिका को दशार्ता है।

स्वच्छता का यह बाहरी-उन्मुख प्रयास इस संदेश को और अधिक मजबूत करता है कि एक स्वस्थ भारत की शुरूआत स्वच्छ पड़ोस से होती है – और यह कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को इस मामले में एक मानक स्थापित करना चाहिए। जैसे-जैसे पखवाड़ा आगे बढ़ रहा है, पीजीआईने 15 अप्रैल तक के लिए गतिविधियों का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाएँ, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का उत्सव, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक, 'सफाई मित्र सुरक्षा शिविर', 'श्रमदान' गतिविधियाँ, और 15 अप्रैल को एक सम्मान समारोह शामिल हैं।